R.N.I. : UPHIN/2012/52437
Website : www.mantrabharat.com
संस्करण : प्रयागराज
वर्ष : 15
अंक : 165
पृष्ठ : 8
मूल्य : 1.00
रविवार, 22 फरवरी, 2026

जुनून है सच लिखने का

मंत्र भारत

हिन्दी दैनिक

डाक पंजीयन संख्या : एल-2/9/रजि0/ए0डी0/119/15-17

प्रयागराज, लखनऊ, ग्वालियर एवं मुम्बई से एक साथ प्रकाशित एवं प्रतापगढ़, कौशाम्बी, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़ व गोरखपुर से प्रसारित

3 मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं और बालिकाओं को ... 5 डीएम ने तहसील औराई परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों... 7 विजय-रश्मिका की शादी का आलीशान निमंत्रण ...

27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार को घेरा, कहा- इन कमियों की वजह से लटका आरक्षण

भोपाल **(एजेंसी)**। मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो घटनाक्रम सामने आया है, वह केवल एक कानूनी विवाद नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल है। मुझे हैरानी है कि हमारी कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27इ आरक्षण देने की प्रक्रिया पूरी कर दी थी,

और 27इ आरक्षण प्रदेश में लागू भी हो गया था, लेकिन कुछ लोगों ने छल करते हुए इसे रोकने का काम किया, नतीजतन आज तक हमारे ओबीसी समाज को उसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा है। आखिर यह कैसी व्यवस्था है, जिसमें एक सरकार अधिकार देती है, तो दूसरे दल की सरकार इसे लागू नहीं करने को अपनी उपलब्धि मानती है। हाईकोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। प्रदेश के युवाओं को उम्मीद थी कि अब शीर्ष अदालत में ठोस तैयारी के साथ सरकार अपना पक्ष रखेगी और वर्षों से लटका विवाद सुलझेगा। लेकिन जो खबरें सामने आईं, वे चौंकाने वाली हैं। कभी सरकार के वकील अधूरी तैयारी के साथ पहुंचे, तो कभी समय पर उपस्थित ही नहीं हुए। क्या यह संवेदनशील मुद्दा इतनी लापरवाही से निपटाने लायक था? क्या सरकार को अंदाज़ा नहीं कि इस फैसले पर लाखों भर्तियां, हजारों परिवारों की उम्मीदें और पूरे समाज का विश्वास टिका हुआ है? अब सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस हाईकोर्ट को भेज दिया है और विशेष पीठ बनाकर तीन महीने में निर्णय लेने को कहा है। सवाल यह है कि यदि शुरुआत से ही गंभीरता दिखाई जाती, तो क्या यह स्थिति बनती? क्या युवाओं को वर्षों तक असमंजस में रखा जाना चाहिए था? 2019 से शुरू हुआ यह विवाद आज 2026 तक खिंच चुका है। कितनी पीढ़ियां इस इंतज़ार में अपनी आयु सीमा पार कर चुकीं, कितनी भर्तियां अटक गईं, इसका हिसाब कौन देगा? सरकार बार-बार दावा करती है कि वह पिछड़े वर्ग के साथ खड़ी है। लेकिन यदि 27इ आरक्षण का लाभ वास्तविक रूप से लागू ही नहीं हो पा रहा, तो यह समर्थन केवल भाषणों तक सीमित क्यों दिखाई देता है? यदि नीति सही थी, तो उसकी कानूनी तैयारी पुख्ता क्यों नहीं थी? यदि सामाजिक न्याय का संकल्प था, तो अदालत में पक्ष मजबूती से क्यों नहीं रखा गया? क्या हमारे देश में न्याय मिलना इतना कठिन हो गया है? या फिर न्याय की राह में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी सबसे बड़ी बाधा बन रही है? प्रदेश का ओबीसी वर्ग जवाब चाहता है। युवा जानना चाहते हैं कि उनका अधिकार कब तक अदालतों की तारीखों में उलझा रहेगा। सरकार को स्पष्ट करना होगा कि वह केवल घोषणा करती है या वास्तव में उसे लागू कराने की क्षमता और गंभीरता भी रखती है। अब समय आ गया है कि सरकार राजनीतिक बयानबाज़ी से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई दिखाए। सामाजिक न्याय केवल घोषणा से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, कानूनी तैयारी और जवाबदेही से स्थापित होता है। मध्यप्रदेश का ओबीसी समाज अब प्रतीक्षा नहीं, परिणाम चाहता है।

बता दें कि मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। वर्ष 2019 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को वापस भेज दिया है और कहा है कि अंतिम फैसला हाईकोर्ट ही करेगा।

डोनाल्ड ट्रम्प के हर मूव का कर रहे अध्ययन, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले के बाद भारत सरकार सतर्क

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारतीय सरकार अमेरिकी टैरिफ और उनके प्रभावों से संबंधित घटनाक्रमों का अध्ययन कर रही है। यह प्रतिक्रिया अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन द्वारा लगाए गए पारस्परिक टैरिफ को रद्द करने के बाद आई है। 6-3 के विभाजित फैसले में, अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने फैसला सुनाया कि ट्रम्प कांग्रेस की मंजूरी के बिना आईईईपीए 1974 के तहत टैरिफ नहीं लगा सकते। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'हमने कल (शुक्रवार) अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ संबंधी फैसले पर ध्यान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि अमेरिकी प्रशासन द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। हम इन सभी घटनाक्रमों के प्रभावों का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले दिन में केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि केंद्र इस फैसले की जांच करेगा और वाणिज्य मंत्रालय या विदेश मंत्रालय इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देंगे। जोशी ने कहा कि मैंने मीडिया में पढ़ा है कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ फैसला सुनाया है और भारतीय सरकार उसका अध्ययन करेगी, और जो भी प्रतिक्रिया देनी होगी, वह वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा दी जाएगी, न कि मेरे द्वारा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके कुछ टैरिफ संबंधी कार्रवाइयों को समाप्त कर दिया और एक अस्थायी आयात अधिभार लगाने की घोषणा की। यह अस्थायी 10 प्रतिशत आयात शुल्क 24 फरवरी को पूर्वी मानक समय के अनुसार रात 12:01 बजे से प्रभावी होगा। कुछ टैरिफ हटाने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर करके अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले सामानों पर 10 प्रतिशत 'अस्थायी आयात अधिभार' को 'मूल्य-आधारित शुल्क' के रूप में लागू किया।

भारत-ब्राजील व्यापार समझौता : हमारी जुगलबंदी से बढ़ेगी ग्लोबल साउथ की ताकत

पीएम मोदी ने कहा- आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश साथ

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत और ब्राजील का एक साथ आना अंतरराष्ट्रीय मंच पर वैश्विक दक्षिण की आवाज को कैसे मजबूत करता है। उन्होंने समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार का आह्वान किया और इस दिशा में मिलकर काम करने के लिए भारत और ब्राजील के संकल्प की पुष्टि की। उन्होंने ये बातें राष्ट्रीय राजधानी में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं।

उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत और ब्राजील की साझेदारी मजबूत और प्रभावशाली रही है। लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते, हम वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। जब भारत और ब्राजील मिलकर काम करते हैं, तो वैश्विक दक्षिण की आवाज और भी मजबूत और आत्मविश्वास से भरी हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हमारा मानना है कि सभी समस्याओं का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। भारत और ब्राजील इस बात पर एकमत हैं कि आतंकवाद और उसके समर्थक पूरी मानवता के शत्रु हैं।

हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारे समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार आवश्यक है। हम इस दिशा में मिलकर काम करना जारी रखेंगे।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि, सटीक खेती और जैव उर्वरक के क्षेत्रों में सहयोग से दोनों देशों की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ धातुओं पर हुआ समझौता एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। रक्षा क्षेत्र में भी हमारा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। यह आपसी विश्वास और रणनीतिक तालमेल का एक बेहतरीन उदाहरण है। हम इस लाभकारी साझेदारी को और मजबूत करना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, 'स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्रों में भी सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। हम भारत से ब्राजील को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए काम करेंगे।

अगले पांच वर्षों में घुसपैठियों को न केवल मतदाता सूची से बल्कि देश से भी निकाल दिया जाएगा : अमित शाह

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को जोर दिया कि अगर भारत नक्सलियों से मुक्त हो सकता है, तो वह घुसपैठियों से भी मुक्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगले पांच वर्षों में अवैध प्रवासियों को न केवल मतदाता सूची से बल्कि देश से भी निकाल दिया जाएगा। शाह असम पुलिस की 10वीं बटालियन के नए परिसर की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। बटालियन के बारे में उन्होंने कहा कि इसका निर्माण घुसपैठियों के अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि पर किया जाएगा।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता ने एक बार कहा था कि घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन ''कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि अवैध प्रवासी उसका वोट बैंक हैं।'' उन्होंने कहा, ''अतिक्रमण की गई जमीनों से घुसपैठियों को निकालना ही काफी नहीं है, उन्हें भारत से बाहर भी भेजना होगा।'' शाह ने कहा कि अगले पांच वर्षों में असम पूर्व और पूर्वोत्तर भारत का औद्योगिक केंद्र बन जाएगा। असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए चुनाव मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है।

अंतरिम व्यापार समझौते पर रोक लगे, नए सिरे से बातचीत हो-कांग्रेस

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अब अमेरिका के साथ अंतरिम व्यापार समझौते को स्थगित कर दिया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दो टूक कहना चाहिए कि अमेरिकी पक्ष से स्पष्टीकरण आने तक भारत की तरफ से आयात उदारीकरण नहीं होगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार को इस समझौते पर अमेरिका के साथ फिर से बातचीत करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के लाखों किसानों की आजीविका पर नकारात्मक असर नहीं हो।

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक 'टैरिफ' को खारिज कर दिया, जिससे उन्हें उनके आर्थिक एजेंडे के मुद्दे पर बड़ा झटका लगा है। न्यायाधीशों ने बहुमत से कहा कि संविधान बहुत स्पष्ट रूप से अमेरिकी कांग्रेस को कर लगाने की शक्ति देता है, जिसमें 'टैरिफ' भी शामिल है। रमेश ने कहा, ''अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद इस अंतरिम समझौते को स्थगित कर दिया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अमेरिका की तरफ से स्पष्टीकरण आने तक हम आयात उदारीकरण नहीं करेंगे।''

उन्होंने यह भी कहा, ''इस व्यापार समझौते को लेकर नए सिरे से बातचीत होनी चाहिए।'' रमेश ने कहा, ''राष्ट्रपति ट्रंप ने गत दो फरवरी को व्यापार समझौते की पहली घोषणा की और कहा कि प्रधानमंत्री के आग्रह पर यह समझौता हो रहा है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने जल्दबाजी क्यों की?'' उन्होंने दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में दिए भाषण से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री ने आनन-फानन में व्यापार समझौते के लिए ट्रंप से आग्रह किया। रमेश ने कहा, ''प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री और सरकार को दिसंबर से जानकारी थी कि इस मामले में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का निर्णय आने वाला है और हो सकता है कि निर्णय ट्रंप के खिलाफ का सकता है। फिर ट्रंप पर दबाव क्यों डाला गया कि समझौते की घोषणा की जाए?'' उन्होंने कहा, ''ट्रंप ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भारत-अमेरिका समझौते पर कोई असर नहीं होगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के इस बयान से सहमत हैं?''

'कांग्रेस देश विरोधी है': एआई समिट में हंगामे पर शहजाद पूनावाला का तीखा हमला

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'एआई इम्पैक्ट समिट' में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन पर सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कांग्रेस को 'देश विरोधी' करार दिया है।

पुणे में मीडिया से बात करते हुए पूनावाला ने कहा कि भारत मंडपम जैसे वैश्विक मंच पर 'शर्टलेस' प्रदर्शन करके कांग्रेस ने अपना असली चरित्र दिखा दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'कांग्रेस ने केवल कपड़ों के बिना प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि यह दिखाया कि वे चरित्रहीन, निष्ठाहीन और बुद्धिहीन हो चुके हैं। आज पूरा देश उन्हें काला झंडा दिखा रहा है और उनके अपने गठबंधन सहयोगी भी इस व्यवहार से किनारा कर रहे हैं।' पूनावाला ने आगे कहा कि अब यह पार्टी 'इंडियन नेशनल कांग्रेस' नहीं रही, बल्कि 'एंटी-नेशनल कांग्रेस' बन गई है।

बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी की टीम पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को बीजेपी या प्रधानमंत्री से कोई समस्या है, तो उन्हें बीजेपी कार्यालय, जंतर-मंतर या पीएमओ के बाहर विरोध करना चाहिए था। उन्होंने सवाल उठाया, 'बीजेपी का विरोध करते-करते आप देश के विरोधी कब से हो गए? जब दुनिया भर के प्रतिनिधि एआई शिखर सम्मेलन में भारत की शक्ति देख रहे थे, तब कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की।'

शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी का इतिहास हमेशा देश की उपलब्धियों का विरोध करने का रहा है। उन्होंने कहा, 'चाहे वह यूपी की सफलता हो, वैक्सीन निर्माण हो, या क्रिकेट मैच में जीत–कांग्रेस हर उपलब्धि पर विरोध करती है। यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है।'

यह विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम के बाहर अपनी शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। उनकी शर्ट पर 'समझौतावादी प्रधानमंत्री' जैसे नारे लिखे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि केंद्र सरकार देश की पहचान के साथ समझौता कर रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लोक सेवक के काम में बाधा डालने और सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन की विभिन्न धाराओं (जो गैर-जमानती हैं) के तहत मामला दर्ज किया है।

प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने फिर 'आत्मसमर्पण' करेंगे : कांग्रेस

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। कांग्रेस ने अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए शनिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व्यापार समझौते पर अमेरिका से दोबारा बातचीत नहीं कर सकते और वह फिर से समर्पण कर देंगे। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक शुल्क को खारिज कर दिया, जिससे ट्रंप के आर्थिक एजेंडे को बड़ा झटका लगा है। न्यायाधीशों ने बहुमत के फैसले में कहा कि संविधान बहुत स्पष्ट रूप से अमेरिकी कांग्रेस (संसद) को कर लगाने की शक्ति देता है, जिसमें शुल्क भी शामिल है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''प्रधानमंत्री समझौता कर चुके हैं। उनका विश्वासघात अब उजागर हो गया है। वह (व्यापार समझौते पर) दोबारा बातचीत नहीं कर सकते। वह फिर से समर्पण कर देंगे।''

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''बिना सिर-पैर वाली विदेश नीति या एकतरफा समर्पण? जिस ''ट्रैप डील'' ने भारत से भारी रियायतें लीं, मोदी सरकार ने उसमें फंसने से पहले शुल्क पर अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया?'' उन्होंने कहा, ''संयुक्त वक्तव्य में भारत को होने वाले कई अमेरिकी निर्यातों पर शून्य शुल्क की बात कही गई है जिससे भारतीय कृषि क्षेत्र का द्वार अमेरिकी वस्तुओं के लिए खुल जाएगा। साथ ही, 500 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामान आयात करने की योजना, हमारी ऊर्जा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले रूसी तेल की खरीद पर रोक लगाने की प्रतिबद्धता और डिजिटल मोर्चे पर कई कर रियायतों की बात संयुक्त वक्तव्य में कही गई है।''

उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि भारत के राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता करने के लिए उन पर किसने दबाव डाला? क्या यह एप्स्टीन फाइलें थीं?'' उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत सरकार अपनी गहरी नींद से जागेगी और एक निष्पक्ष व्यापार समझौता करेगी जो 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के आत्मसम्मान और हमारे किसानों, श्रमिकों, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करेगा? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि यह समझौता एक कठिन परीक्षा की तरह बन गया है जिसका सामना देश को प्रधानमंत्री के आत्मसमर्पण के कारण करना पड़ रहा है। रमेश ने अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए यह सवाल भी किया कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुनिश्चित किया कि दो फरवरी 2026 की रात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की घोषणा करें? अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ट्रंप ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले का अमेरिका और भारत द्वारा इस महीने की शुरुआत में घोषित व्यापार समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ अपने ''अच्छे'' संबंधों पर भी चर्चा की।

उन्होंने कहा, ''कोई बदलाव नहीं होगा। वे (भारत) शुल्क का भुगतान करेंगे और हम शुल्क नहीं देंगे। इसलिए भारत के साथ समझौता यही है कि वह शुल्क देगा यह पहले की स्थिति से उलट है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन अमेरिका के संदर्भ में वह जिनके समकक्ष थे उनसे कहीं अधिक होशियार थे। वह हमें नुकसान पहुंचा रहे थे। इसलिए हमने भारत के साथ एक समझौता किया। अब यह एक निष्पक्ष समझौता है और हम उन्हें शुल्क नहीं दे रहे हैं, जबकि वे शुल्क दे रहे हैं। हमने थोड़ा बदलाव किया।'' ट्रंप ने कहा, ''भारत के साथ समझौता जारी हैष्ठ सभी समझौते जारी हैं, हम बस इसे एक अलग तरीके से करेंगे।'' इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और भारत ने व्यापार पर एक अंतरिम समझौते के लिए एक रूपरेखा पर पहुंचने की घोषणा की। ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर लगाए गए 25 प्रतिशत दंडात्मक शुल्क को हटा दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने रूस से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का आयात बंद करने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों को खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ीं मुश्किलें, न्यायालय ने यौन शोषण केस में दिया एफआईआर का आदेश

प्रयागराज। जनपद स्थित बलात्कार एवं यौन शोषण विरोधी विशेष न्यायालय के सहायक न्यायाधीश ने पुलिस को ज्योतिष पीठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोपों के संबंध में

एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश विनोद कुमार चौरासिया ने पहले की पुलिस निष्क्रियता को खारिज करते हुए झोआंसी पुलिस स्टेशन को मामला दर्ज करने और जांच शुरू करने का निर्देश दिया। इस फैसले से उस विवाद में और भी तीव्रता आ गई है जो माघ मेले के दौरान इन आरोपों के सामने आने के बाद से इस क्षेत्र में व्याप्त है। यह मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा सीआरपीसी की धारा 173(4) के तहत 28 जनवरी को दायर याचिका से शुरू हुआ। ब्रह्मचारी ने स्वामी के आश्रम पर बच्चों के सुनियोजित यौन शोषण का आरोप लगाया और दावा किया कि वाराणसी के विद्यामठ में 'गुरु सेवा' की आड़ में नाबालिगों को जबरन यौन कृत्यों के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने सबूत के तौर पर एक सीडी प्रस्तुत की और लगभग 20 पीड़ित बच्चों का जिक्र किया, जिन्होंने उनसे संपर्क किया था। उन्होंने धार्मिक आड़ में छिपे शोषण के एक पैटर्न को उजागर किया। 13 फरवरी को अदालत ने दो नाबालिग पीड़ितों के वीडियो रिकॉर्ड किए गए बयान दर्ज किए, जिनके आधार पर आदेश जारी किया गया। पुलिस रिपोर्ट से संतुष्ट न होने पर न्यायाधीश ने इन बयानों की समीक्षा करने के बाद एफआईआर जारी करने से पहले फैसला सुरक्षित रख लिया। इस प्रक्रियात्मक सख्ती से पीओसीएसओ के तहत बाल संरक्षण कानूनों को प्राथमिकता मिलती है, जो पुलिस की धीमी कार्रवाई के बीच एक चर्चित धार्मिक व्यक्ति के खिलाफ दुर्लभ न्यायिक हस्तक्षेप का प्रतीक है।

आगामी त्यौहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सम्भ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक

सिद्धार्थनगर। जिले के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र में आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी विवेकानंद मिश्रा व क्षेत्राधिकारी मयंक द्विवेदी ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रहरियों एवं गणमान्य नागरिकों के साथ विस्तृत वार्ता कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक को संबोधित करते हुए उपजिलाधिकारी विवेकानंद मिश्रा ने कहा कि पूर्व वर्षों की भांति इस बार भी होली का पर्व परंपरागत तरीके से ही मनाया जाएगा तथा किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि होलिका दहन पूर्व से चिन्हित एवं प्रस्तावित स्थलों पर ही किया जाएगा। जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि किसी क्षेत्र में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो प्रशासन द्वारा उसका त्वरित समाधान कराया जाएगा।

वहीं क्षेत्राधिकारी मयंक द्विवेदी ने बताया कि तहसील क्षेत्र में कुल 163 स्थानों पर होलिका दहन प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि होली आपसी भाईचारे और खुशियों का पर्व है। यदि किसी समुदाय का व्यक्ति होली नहीं खेलना चाहता है तो उसके साथ जबरन रंग न खेलें। उन्होंने सभी से सतर्कता बरतने और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।

सीओ ने होली के अवसर पर अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, भंडारण एवं सेवन पर सख्त प्रतिबंध लगाने की बात कही। उन्होंने आश्वस्त किया कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम प्रहरियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बीते वर्ष होली के दिन बाणगंगा बैराज पर हुई दुर्घटना का भी उल्लेख किया गया। प्रशासन ने इस वर्ष एहतियातन होली के दिन बैराज के उत्तर एवं दक्षिण दिशा में नदी में स्नान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। साथ ही बैराज पर प्रकाश व्यवस्था, एनाउंसमेंट और पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने हेतु प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

बैठक में चेयरमैन प्रतिनिधि रवि अग्रवाल, सुधांशु बोरा, सूर्य प्रकाश पाण्डेय, शिव प्रसाद वर्मा, सौरभ गुप्ता, शैलेन्द्र कौशल, मनोज कुमार गुप्ता, महेश कसौधन, दिलीप वर्मा, वीरेन्द्र मोदनवाल, संजय दूबे, निसार अहमद, रोहित मद्धेशिया, अल्ताफ हुसैन, वकील खान, वीरेंद्र प्रताप जायसवाल, रमेश मणि त्रिपाठी, संतोष पासवान, विवेक पाण्डेय, अजय चौधरी, सुभाष यादव, मेजर सिंह चौहान, पिंटू सिंह, बबलू गौड़, प्रमोद श्रीवास्तव, वीरेंद्र गौड़, राजू बाबा, शौक़ी लाल, राम मिलन चौधरी, ओमप्रकाश यादव, पिंटू पटेल सहित एसडीओ विद्युत विनोद कुमार, लिपिक राजेश त्रिपाठी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।

महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मरक्षा, दहेज उत्पीड़न आदि अपराध से बचाव के बारे में पुलिस ने किया जागरूक

सिद्धार्थनगर। जिले में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सशक्त बनाने हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5.0 के अन्तर्गत शनिवार को जन चौपाल बहू-बेटी सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक महाजन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान के संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ मयंक द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में कार्यक्रम हुआ शोहरतगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह के निर्देशन में शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रमवापुर तिवारी में बहू-बेटी सम्मेलन आयोजित कर छात्राओं एवं महिलाओं को सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मरक्षा, अपराध से बचाव, दहेज उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट तथा महिला संबंधित मामलों में सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही पीड़िताओं की काउंसलिंग भी की गई।कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति केंद्र की जानकारी देते हुए बताया गया कि उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र में महिलाएं अपनी समस्याएं दर्ज करा सकती हैं। महिलाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 वुमेन पावर लाइन, 181महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 (पुलिस हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड केयर लाइन, 108 एम्बुलेंस, 101अग्निशमन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन एवं 1930 साइबर हेल्पलाइन की जानकारी भी दी गई। साथ ही मिशन शक्ति 5.0 के स्टीकर चस्पा किए गए।लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रमवापुर तिवारी के प्रधानाचार्य अंबिकेश शुक्ल एवं अध्यापिका प्रीति की मौजूदगी में कुल 80 बालिकाओं एवं 40 बालकों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में यातायात नियमों के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान प्रधानाचार्य अंबिकेश शुक्ल, शिक्षिका प्रीति, उप निरीक्षक राजकुमार यादव, हे0का0 अविनाश सिंह, का0 पवन मौर्य एवं म0का0 शोभा भारती के साथ शिक्षक मौजूद रहे।

भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने फूंका राहुल गांधी का पुतला

कौशाम्बी। एआई समिट में कांग्रेसियों की ओर से अर्धनग्न प्रदर्शन मामले में शनिवार को भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंक कर विरोध जताया। जिलाध्यक्ष शिव प्रताप उर्फ रिंकू मौर्य ने बताया कि एआई समिट के दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कपड़े उतारकर प्रदर्शन करते हुए नंगा नाच किया था। कार्यकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। कांग्रेसियों के इस कृत्य पर भाजपा के शीर्ष नेताओं के निर्देश पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंका है। इस मौके पर संगठन के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

किसानों को क्षतिपूर्ति और सहायता राशि का वितरण हुआ वितरण

सिद्धार्थनगर। जिले में योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा राजस्व एवं आपदा विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को क्षतिपूर्ति और सहायता राशि का वितरण लगातार किया जा रहा है।इसी क्रम में शनिवार को जिले की बांसी व शोहरतगढ़ तहसील परिसर सहित पूरे जनपद की सभी तहसील सभागार में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बांसी से विधायक पूर्व मंत्री जय प्रताप सिंह व शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने दर्जनों किसान परिवारों को कुल कई लाख की सहायता राशि के चेक वितरित किए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी न्यायिक ज्ञान प्रकाश उपजिलाधिकारी निखिल चक्रवर्ती विवेकानंद मिश्रा एवं तहसीलदार बांसी पीयूष श्रीवास्तव सहित शोहरतगढ़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में यह आर्थिक सहायता किसानों के परिवारों के लिए संबल का कार्य करेगी और उन्हें नई ऊर्जा प्रदान करेगी। उन्होंने किसानों के हित में संचालित योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया।उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि ही प्रदेश और देश की समृद्धि का आधार है। सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनके उत्थान के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में तीन युवक घायल, रेफर

सिद्धार्थनगर। जिले के शोहरतगढ़ चेतिया मार्ग पर शुक्रवार की रात खरगवार मोड़ के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत में तीन युवक गम्भीर रूप से घायल हो गये। पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शोहरतगढ़ पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने दो घायलों के सिर में गम्भीर चोट व पैर की हड्डी टूट जाने से हालत गम्भीर देख माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कालेज सिद्धार्थ नगर भेज दिया ।शोहरतगढ़ चेतिया मार्ग पर शुक्रवार की रात खरगवार मोड़ के पास दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई । भिड़ंत इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार गिरकर गम्भीर रूप से घायल हो गये।एक बाइक पर सवार दोनों युवक सड़क के नीचे खाई में चले गये। सिद्धार्थनगर थानाक्षेत्र ग्राम मदनपुर चुरीहारी निवासी प्रिंस रस्तोगी पुत्र संजय और आबिद पुत्र हामिद अली नकथर नहर से होते हुए जिला मुख्यालय जा रहे थे।दूसरा बाइक सवार सुरेश यादव पुत्र राम तीरथ शोहरतगढ़ थानाक्षेत्र ग्राम डफरा निवासी बाइक से शोहरतगढ़ की तरफ जा रहे थे।इस घटना में सुरेश यादव व आबिद अली के सिर में गम्भीर चोट व पैर की हड्डी टूट जाने पर दोनों को एम्बुलेंस से माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कालेज भेज दिया गया। इस संबंध में शोहरतगढ़ थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह ने कहा कि दो बाइक की आमने सामने भिड़त हुई है। दोनों बाइक पर सवार तीन युवक घायल हो गये है।तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मिलावट की आशंका पर 373 लीटर सरसों तेल सीज

कौशाम्बी। होली पर्व के मद्देनजर शनिवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी तेज कर दिया है। मूरतगंज में सरसों तेल में मिलावट की आशंका पर नमूना लेते हुए उसे सीज कर दिया। एक मिष्ठान की दुकान से मिल्क केक का नमूना लेकर जांच का भेज दिया। खाद्य सुरक्षा टीम होली पर्व को लेकर संजीदा हो गया है। टीम द्वारा जिले में मिलावटखोरी रोकने के लिए लगातार छापेमारी की गई है। शनिवार को टीम द्वारा मूरतगंज स्थित दिलीप किराना स्टोर से सरसों तेल का नमूना लेकर कुल 373 लीटर तेल (कुल मूल्य-52220रूपए) सीज किया गया। इसके बाद मूरतगंज स्थित मंगल स्वीट्स से मिल्क केक का नमूना लिया गया। टीम ने बताया कि होली के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान के दौरान विभाग द्वारा कुल 14 नमूने लिए गए है। टीम की छापेमारी से मूरतगंज बाजार में शनिवार को दिनभर हड़कम्प मचा रहा। खाद्य सचल दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नितिन कुमार, डॉ. भरत कुमार मिश्र व अरविंद कुमार सिंह शामिल रहे।

कांग्रेस के शर्टलेस विरोध प्रदर्शन पर भाजपा का पलटवार, महाराष्ट्र में सड़कों पर संग्राम

मुम्बई **(एजेंसी)**। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और युवा विंग के सदस्यों ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को बाधित करने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस की निंदा करते हुए कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली, सूरत, महाराष्ट्र के मुलुंड, हैदराबाद और अन्य स्थानों पर प्रदर्शन हुए, जिनमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की निंदा करते हुए नारे लगाए और तख्तियां लहराईं। मुलुंड में, प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए, जब वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के मामले में नई जमानत देने के लिए ठाणे जा रहे थे।

शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी को 'राष्ट्र-विरोधी' करार दिया। यह बयान तब आया जब भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजधानी के भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में विरोध प्रदर्शन किया। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस कृत्य से कांग्रेस ने अपना असली चरित्र दिखा दिया है, जिसकी उसके कई सहयोगी दलों ने भी निंदा की है। पूनावाला ने एएनआई को बताया कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ बिना शर्ट के विरोध प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने यह भी दिखा दिया है कि वे चरित्रहीन, बेस्वाद, निष्ठाहीन, भावनाहीन और बुद्धिहीन हैं। इस कृत्य के कारण पूरा देश उन्हें काले झंडे दिखा रहा है। यहां तक कि उनके सहयोगी दल भी उन्हें लाल झंडे दिखा रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि कांग्रेस राष्ट्र-विरोधी है। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए आगे कहा कि भाजपा के खिलाफ कोई भी विरोध प्रदर्शन वैश्विक शिखर सम्मेलन के बजाय भाजपा कार्यालय, जंतर-मंतर या सेवा तीर्थ (प्रधानमंत्री कार्यालय) में किया जाना चाहिए था।

ये विरोध प्रदर्शन नई दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन में हुई एक घटना के बाद शुरू हुए हैं, जहां लगभग 10 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते हुए बिना शर्ट पहने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों वाली सफेद टी-शर्ट पहनी हुई थी या अपने साथ रखी हुई थी। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कार्यकर्ताओं को इस उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन को बाधित करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें सैम अल्टमैन और सुंदर पिचाई सहित वैश्विक प्रौद्योगिकी जगत के नेता शामिल थे।

बॉम्बे हाई कोर्ट की नौसेना को फटकार, ये कैसी खुफिया एजेंसी? नाक के नीचे बन गई 20 मंजिला इमारत

मुम्बई **(एजेंसी)**। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को नौसेना की उस चुनौती पर सुनवाई करते हुए 'नौसेना खुफिया विभाग की विफलता' का जिक्र किया, जिसमें नौसेना कोलाबा में आईएनएस शिकरा के पास बन रही 20 मंजिला से अधिक ऊंची इमारत को चुनौती दी गई है। नौसेना इसे नौसेना प्रतिष्ठान के लिए संभावित खतरा मानती है। कोर्ट ने कहा कि अगर 2024 में शुरू हुआ यह निर्माण का य पहले ही उजागर होने के बजाय अब तक अनदेखा किया गया है, तो यह नौसेना की ओर से एक बड़ी चूक होगी। न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे और अभय मंत्री की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया, यह नौसेना की खुफिया जानकारी में स्पष्ट विफलता को दर्शाता है। पीठ ने डेवलपर को नौसेना के स्थानीय सैन्य प्राधिकरण द्वारा दायर याचिका की अंतिम सुनवाई तक किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार का निर्माण न करने का निर्देश भी दिया।

अदालत ने कहा कि जब ये टावरनुमा इमारतें 63 मीटर की ऊंचाई तक बनाई जा रही हैं, तो हमें आश्चर्य है कि याचिकाकर्ता की खुफिया एजेंसी ने इमारत के डेवलपर के निर्माण पर ध्यान क्यों नहीं दिया, जिसने धीरे-धीरे एक के बाद एक मंजिलें बनाते हुए 2024 में ग्राउंड प्लस 19 तक का निर्माण पूरा कर लिया। पीठ ने डेवलपर और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को नौसेना की याचिका का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, साथ ही इस बात पर चिंता व्यक्त की कि इमारत नौसेना की संपत्ति के सामने स्थित है। पीठ ने

डेवलपर और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को नौसेना की याचिका का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, साथ ही इस बात पर चिंता व्यक्त की कि इमारत नौसेना की संपत्ति के सामने स्थित है।

अदालत ने कहा कि डेवलपर अपनी संपत्ति का विकास अपने जोखिम पर करेगा। 'यदि अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एनओसी अनिवार्य है, तो हम उक्त मंजिलों को ध्वस्त करने का निर्देश देंगे। यदि हम अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नगर निगम या तो मिलीभगत कर रहा है या उसकी ओर से लापरवाही बरती गई है, या यदि परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि उसने याचिकाकर्ता की एनओसी लिए बिना ओसी/सीसी जारी करके गलती की है। पीठ ने यह भी चेतावनी दी, 'यदि परिस्थितियां ऐसा संकेत देती हैं, तो हम नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन का निर्देश देने में संकोच नहीं करेंगे। पीठ ने निर्देश दिया कि डेवलपर 53 मीटर से ऊपर की मंजिलों के लिए फ्लैट नहीं बेचेगा या तृतीय-पक्ष अधिकार नहीं बनाएगा और खरीदारों को याचिका लंबित होने, अंतरिम आदेश और किसी भी प्रतिकूल परिणाम के जोखिम के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करेगा, जो ऐसे खरीदारों पर भी लागू होगा।

हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की भव्य तैयारी, सीएम पुष्कर धामी ने 234 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की नींव रखी

देहरादून **(एजेंसी)**। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को कुंभ मेला-2027 की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए हरिद्वार पहुंचे। कुंभ मेला नियंत्रण भवन (सीसीआर) पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला-2027 के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित 34 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी। अनुमानित 234.55 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इन स्थायी विकास कार्यों का उद्देश्य कुंभ मेले का सफल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करना और साथ ही हरिद्वार शहर के दीर्घकालिक विकास को मजबूत करना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी तैयारियां जारी हैं और 2025 की चारधाम यात्रा के समापन के तुरंत बाद हमने 2026 की चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी थीं और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। हम हितधारकों से नियमित रूप से बैठकें कर रहे हैं और यात्रा के आयोजन में शामिल सभी लोगों से सुझाव ले रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस बार यात्रा थोड़ी जल्दी आयोजित की जा रही है। अप्रैल में, जब स्कूल बंद होते हैं और भारी भीड़ होती है, तब कुंभ मेले के द्वार खुलेंगे। इसलिए, आगंतुकों को सुखद यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं...2027 कुंभ मेले के लिए आज एक समीक्षा बैठक हुई और लगभग ढाई सौ करोड़ रुपये की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। धामी ने आगे कहा कि सभी कार्य समय पर पूरे होने चाहिए। कुंभ मेले की सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित होनी चाहिए और सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। सभी विभागों को एक-दूसरे के साथ समन्वय में काम करना चाहिए। इस बीच, अगले वर्ष हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के मद्देनजर, देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए मेला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं।

कुंभ मेले के दौरान रेल मार्ग से बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने की संभावना को देखते हुए, हरिद्वार और आसपास के अन्य रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुविधाएं और आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास तेज कर दिए गए हैं।

कर्नाटक के भाजपा विधायक रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, गिरफ्तार

बेंगलुरु **(एजेंसी)**। कर्नाटक के शिरहट्टी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक चंद्रू लामणि को कर्नाटक लोकायुक्त ने कथित तौर पर 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। यह राशि कथित तौर पर 11 लाख रुपये की कुल मांग का हिस्सा थी। अधिकारियों ने बताया कि लामणि को पहले एक गुप्त ऑपरेशन के बाद पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और उसके बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में उनके दो निजी सहायकों को भी हिरासत में लिया गया है। लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार, गडग जिले में सिंचाई विभाग की एक लघु परियोजना से संबंधित स्वीकृतियों को सुगम बनाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत मांगी गई थी। इस कार्य में सड़क के दोनों किनारों पर एक रिटेनिंग दीवार का निर्माण शामिल था, जिसे एक ठेकेदार को सौंपा गया था। गडग निवासी प्रथम श्रेणी के ठेकेदार विजय पुजार ने भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों से संपर्क किया, क्योंकि परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरी दिलाने के बदले उनसे कथित तौर पर 11 लाख रुपये मांगे गए थे। शिकायत की पुष्टि करने के बाद, लोकायुक्त पुलिस ने शनिवार को जाल बिछाया। इस कार्रवाई के दौरान, लामानी को कथित तौर पर मांगी गई राशि में से 5 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया। यह कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस की एक टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में की। अधिकारियों ने बताया कि कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए और उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई।

दिल्ली में टेरर अलर्ट के बाद बड़ा एक्शन, पंजाब-कश्मीर में 2 आईईडी बरामद, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हाई अलर्ट जारी करने और पाकिस्तान स्थित संगठन लश्कर-ए-तैबा द्वारा दिल्ली में संभावित आतंकी हमले की चेतावनी देने के बाद पंजाब और कश्मीर में दो आईईडी बरामद किए गए। हालांकि अधिकारियों ने आईईडी बरामदगी को आतंकी साजिश की चेतावनी से नहीं जोड़ा है, लेकिन घटनाओं के समय को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पंजाब में, शुक्रवार को अमृतसर के राय्या पुलिस चौकी के पास एक संदिग्ध बैग में एक आईईडी बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि बम निरोधक दस्ते को तुरंत मौके पर भेजा गया और आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया।

लाल किले के पास संभावित आतंकी खतरे की चेतावनी देने वाली सूचनाओं के बाद राष्ट्रीय राजधानी में खुफिया अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों का कहना है कि आतंकवादी चांदनी चौक इलाके के एक मंदिर को निशाना बना सकते हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार, लाल किले के आसपास के इलाके और चांदनी चौक के कुछ हिस्से समेत कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैबा के निशाने पर हैं।

सूचनाओं से संकेत मिलता है कि यह संगठन एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण (आईईडी) हमले की योजना बना रहा है और चांदनी चौक इलाके का एक मंदिर संभावित निशाना हो सकता है। सूचनाओं ने यह भी बताया कि यह संगठन कथित तौर पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 6 फरवरी को हुए एक मस्जिद विस्फोट का बदला लेना चाहता है और भारत में एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहा है।

खुफिया सूत्रों ने बताया, 'दिल्ली में लाल किले के सामने विस्फोट का अलर्ट जारी किया गया है। आतंकवादी चांदनी चौक स्थित किसी मंदिर को निशाना बना सकते हैं। लश्कर-ए-तैबा एक आईईडी हमले की साजिश रच रहा है। वे पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 6 फरवरी को हुए मस्जिद विस्फोट का बदला लेने के लिए भारत में एक बड़ा आतंकवादी हमला करने की योजना बना रहे हैं। लश्कर-ए-तैबा देश के प्रमुख मंदिरों को निशाना बना सकता है।'

सीआरपीएफ कर्मी के खाते से 30 हजार रुपये उड़ाए

थरवई। साइबर अपराधियों ने लिंक भेजकर सीआरपीएफ कर्मी के खाते से 30 हजार रुपये उड़ा दिए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार (सीआरपीएफ) ग्रुप केंद्र में कार्यरत धीरेंद्र कुमार आर्य वर्तमान समय में सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र पंडिला में कार्यरत हैं मूल निवासी नई बाजार, बक्सर बिहार के मोबाइल पर 5 फरवरी की रात करीब सात बजे एक संदिग्ध लिंक भेजा गया। लिंक पर क्लिक करते ही उनके बचत खाते से तीस हजार रुपये निकल गए। कुछ ही देर में खाते से धनराशि कटने का मैसेज आने पर उन्हें ठगी का अहसास हुआ।पीड़ित कर्मी ने मामले की लिखित शिकायत थरवई थाने में दी। पुलिस ने अज्ञात साइबर अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि साइबर सेल की मदद से मामले की जांच की जा रही है।

महाप्रबंधक द्वारा वंदे भारत प्रोटोटाइप रेक का निरीक्षण; प्रारंभिक ट्रायल सफलतापूर्वक सम्पन्न

मंत्र भारत संवाददाता

रायबरेली। प्रशान्त कुमार मिश्रा, महाप्रबंधक, एमसीएफ ने कारखाना परिसर में वंदे भारत प्रोटोटाइप रेक का निरीक्षण किया। यह वंदे भारत परियोजना की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

निरीक्षण के दौरान कारखाना परिसर में प्रथम चरण के गति परीक्षण सम्पन्न किए गए। इस अवसर पर एमसीएफ के वरिष्ठ अधिकारीगण, मेसर्स सीमेन्स के प्रतिनिधि तथा अन्य उद्योग सहयोगी उपस्थित रहे। ड्राइवर केबिन से प्रमुख ऑनबोर्ड प्रणालियों का परीक्षण किया गया।

सीमेंस की टीम द्वारा पैंटोग्राफ-वीसीबी (वैक्यूम सर्किट ब्रेकर) संचालन तथा उच्च वोल्टेज आदि का निरीक्षण किया गया। ये सभी क्रियाएं ड्राइवर डेस्क यूनिट से सफलतापूर्वक संचालित की गईं, जिससे प्रणाली की समन्वित कार्यक्षमता एवं परिचालन तत्परता

प्रदर्शित हुई।

एक लघु ट्रायल रन भी किया गया, जिसमें ट्रैक्शन, गति तथा ओवरहेड इक्विपमेंट से लिए गए करंट जैसे प्रमुख परीक्षण मानकों का अवलोकन किया गया। ट्रायल शेड से प्रारंभिक संचालन के दौरान रेक की गति को 10 किमी/घंटा की सीमित निर्धारित गति पर परीक्षण किया गया। ब्रेक प्रतिक्रिया, पैसेंजर एनाउंसमेंट एवं पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की कार्यप्रणाली तथा ट्रैक्शन के दौरान प्रणाली के व्यवहार का भी परीक्षण किया गया।

रेक का विस्तृत निरीक्षण भी किया गया, जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का सत्यापन शामिल था। महाप्रबंधक महोदय ने प्रकाश व्यवस्था के समुचित एलाइनमेंट तथा विद्युत क्यूबिकल्स की वैक्यूम एवं मैग्नेटिक क्लीनिंग के माध्यम से गहन सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी धात्विक अवशेष को हटाकर उच्चतम सुरक्षा एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

यह उपलब्धि एमसीएफ एवं उसके उद्योग सहयोगियों के बीच सुदृढ़ समन्वय एवं सहयोग का प्रतीक है, जो वंदे भारत परियोजना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रशांत कुमार मिश्रा ने इस अवसर पर विवेक खरे, प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता; विजय, मुख्य विद्युत डिजाइन अभियंता; अनुराग दत्त त्रिपाठी, सीडब्ल्यूई/फर्निशिंग; मेसर्स सीमेंस के अनुराग गुप्ता; तथा आरडीएसओ के अनुपम गुप्ता और विष्णु शंकर प्रसाद सहित सभी उद्योग सहयोगियों को उनके समर्पण, समन्वय एवं उत्कृष्ट टीमवर्क के लिए बधाई एवं धन्यवाद दिया।

दिनांक 12 फरवरी 2026 को आयोजित ट्रायल पूर्व निरीक्षण के दौरान मेसर्स सीमेंस के जर्मन अभियंता – क्रिस्टोफ गोएट्ज़, सुसैंड्रा स्पोंसेट एवं सेबास्टियन शोएसर, पदमाकर डीके, सैत कर– भी उपस्थित रहे तथा तकनीकी कार्यवाही में सक्रिय सहभागिता की। यह ट्रायल एमसीएफ की अत्याधुनिक, उच्च गति वाली ट्रेनसेट के निर्माण हेतु उसकी प्रतिबद्धता, नवाचार क्षमता एवं उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को पुनः स्थापित करता है।

श्रीमद्भागवत कथा के चौथे दिन बारह अवतारों का हुआ वर्णन

मंत्र भारत संवाददाता

थरवई। सात दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। कथावाचक पूज्य कृपाशंकर महाराज जी ने श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान विष्णु के बारह अवतारों की कथा का विस्तार से वर्णन किया। उनके प्रवचनों से पंडाल में उपस्थित श्रद्धालु भावविभोर हो उठे।कथावाचक ने मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह सहित अन्य अवतारों के माध्यम से धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अवतार मानव जीवन को सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।कथा का आयोजन सहजीपुर गांव निवासी शारदा प्रसाद द्विवेदी पत्नी सुषमा देवी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैंसंगीतमय भजनों और कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा।

मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं और बालिकाओं को किया जागरूक

मंत्र भारत संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक महाजन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओ की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस प्रशांत कुमार प्रसाद के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी बांसी रोहिनी यादव तथा थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र थाना खेसरहा के कुशल नेतृत्व में मिशन शक्ति टीम उप निरीक्षक जियाउल्लाह, महिला कांस्टेबल अंजली यादव द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत थाना क्षेत्र के ग्राम लोधपुरवा में दहेज उत्पीड़न व 03 नये कानून के बारे में महिला सशक्तिकरण संबंधी बातों को बताते हुए बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत सरकार के विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे मे जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व बहू सम्मेलन अभियान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना रानी लक्ष्मी बाई बाल एवं महिला सम्मान कोष नारी शक्ति वंदन अधिनियम मातृ शक्ति को सम्बल निराश्रित महिला पेंशन योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे मे जानकारी दी गयी तथा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र जहां पर अपनी समस्या को दर्ज करा सकती हैं के बारे में जानकारी दी गई।

मिशन शक्ति फेज 5.0 के विषय मे महिलाओं को महिला सम्वन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन, 108एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर नए कानून के बारे में जानकारी दी गई।

बारात में शामिल होने गए युवक की अज्ञात वाहन की ठोकर से हुई मौत

मंत्र भारत संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के रोमनदेई गांव में शुक्रवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 17 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक बारात में शामिल होने गया था तभी अज्ञात चार पहिया वाहन ने उसे ठोकर मार दी।घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

मिली जानकारी के अनुसार शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के रमवापुर तिवारी निवासी शनि निषाद पुत्र मुकेश निषाद उम्र 17 वर्ष शुक्रवार रात रोमनदेई गांव में आयोजित एक बारात समारोह में शामिल होने गया था। बताया जा रहा है कि रात करीब 10:30 बजे वह सड़क किनारे खड़ा था, तभी तेज रफ्तार अज्ञात चार पहिया वाहन ने उसे जोरदार ठोकर मार दी और मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल शनि को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल शोहरतगढ़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला मुख्यालय स्थित निजी अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गये जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।युवक की असमय मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है वहीं पूरे गांव में शोक व्याप्त है।घटना की जानकारी मिलते ही शोहरतगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। इस संबंध में शोहरतगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है तथा अज्ञात वाहन की पहचान के लिए टीम को लगा दी गई है।

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजन में सैकड़ों ग्रामीणों ने उठाया लाभ

मंत्र भारत संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले में नेशनल मेडिको ज़ ऑर्गनाइजेशन, सिद्धार्थनगर गोरक्ष प्रांत एवं गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के संयुक्त तत्वावधान में शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत चिल्हिया, पल्टादेवी, चौड़ार, खुनुआ बॉर्डर तथा डोहरिया बुजुर्ग में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में क्षेत्र के ग्रामीण एवं जरूरतमंद नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श प्रदान किया गया साथ ही आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि वितरण तथा स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी गईं। बड़ी संख्या में महिलाओं, बुजुर्गों एवं बच्चों ने स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया।समाजसेवी व भाजपा युवा नेता श्याम जायसवाल व आयोजकों ने बताया कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाना है इस सेवा-समर्पित अभियान का मुख्य उद्देश्य है। यह प्रयास जनकल्याण और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को सशक्त बनाना है। स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम के दौरान भाजपा युवा नेता श्याम जायसवाल, विभाग प्रचारक राजीव नयन, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीपक मौर्य, विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत के प्रांत उपाध्यक्ष महादेव प्रसाद, खंड कार्यवाह पंकज कुमार श्रीवास्तव, जिला प्रचार प्रमुख अभय सिंह एवं मंडल महामंत्री अभिषेक चौधरी, बुद्ध सागर पाठक, चौकी प्रभारी खुनुवा वीरेंद्र पासवान, घंश्याम गुप्ता सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहें।

पुलिस ने महिला सुरक्षा के प्रति स्कूली छात्र-छात्राओं को किया जागरूक

मंत्र भारत संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओ की सुरक्षा में चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार प्रसाद व प्रवीन प्रकाश क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष रामदेव थाना गोल्हौरा के निर्देशन में थाना क्षेत्र के कम्पोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय बरगदवा में बालिकाओं को उप निरीक्षण दीनदयाल सिंह, हेड कांस्टेबल शीला पटेल जागरूक किया गया तथा बालिकाओं/महिलाओं को मिशन शक्ति के तहत सरकार के विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे मे जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व बहू सम्मेलन अभियान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना रानी लक्ष्मी बाई बाल एवं महिला सम्मान कोष नारी शक्ति वंदन अधिनियम मातृ शक्ति को सम्बल निराश्रित महिला पेंशन योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे मे जानकारी दी गयी तथा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी थानों पर स्थापित मिशन शक्ति केंद्र जहां पर अपनी समस्या को दर्ज करा सकती हैं के बारे में जानकारी दी गई तथा महिलाओं से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में तथा हेल्पलाईन नं0 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड केयर लाइन108 एम्बुलेंस हेल्प लाइन, 101 अग्निशमन हेल्प लाइन, 14567 एल्डर हेल्पलाइन, 1930 साइबर क्राइम हेल्प लाइन के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।

डीएम की अध्यक्षता में सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस का हुआ आयोजन 41 प्रार्थना पत्र में से 6 का हुआ निस्तारण

मंत्र भारत संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले में शासन के मंशा के अनुरूप आज तहसील नौगढ़ में जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक महाजन की उपस्थिति में सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। तहसील नौगढ़ में आयोजित सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस के आयोजन के अवसर पर राजस्व, विकास, शिक्षा, पूर्ति एवं अन्य विभागों के शिकायतों की सुनवाई जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन, उपजिलाधिकारी नौगढ़ कल्याण सिंह मौर्य द्वारा तथा पुलिस विभाग से सम्बन्धित शिकायतों की सुनवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक महाजन द्वारा किया गया।

जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन द्वारा तहसील समाधान दिवस में पिछले समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों के आख्या का अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि भूमि से संबधित विवाद मौके पर जाकर निरीक्षण कर निस्तारण कराये। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन ने सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस नौगढ़ में उपस्थित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि तहसील समाधान दिवस में प्राप्त हो रही शिकायतों एवं आईजीआरएस

पर प्राप्त शिकायतों का समय से एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ ही शिकायतकर्ता एवं विपक्षी दोनों के समक्ष जांच कर कार्यवाही किया जाये। किसी भी विभाग का तहसील दिवस का कोई भी प्रकरण लम्बित नही होना चाहिए यदि किसी भी विभाग का प्रकरण लम्बित पाया जायेगा तो सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। लेखपाल एवं कानूनगो मौके पर जाकर शिकायत के निस्तारण से पूर्व निरीक्षण कर उसके बाद की आख्या लगायेगे इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नही होनी चाहिए। तहसील में जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र रजिस्टर का अवलोकन किया गया। जिसमें जन्म प्रमाण-2500 तथा मृत्यु प्रमाण-पत्र 1000 जारी करने के प्रकरण लम्बित पाये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उपजिलाधिकारी नौगढ़ को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी। साथ ही चेतावनी दिया गया कि 15 दिवस में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण न होने की दशा में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस के आयोजन के अवसर पर कुल 41 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए जिसमें राजस्व-30, पुलिस विभाग से सम्बन्धित-04, नगर पालिका-01, विकास-01, मनरेगा-02, स्वास्थ्य-01, बाल विकास-02 प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुए। जिलाधिकारी द्वारा राजस्व के 06 प्रार्थना-पत्रों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया गया। तहसील दिवस में प्राप्त शेष शिकायती प्रार्थना पत्रों को तीन दिवस के अन्दर शत-प्रतिशत निस्तारण की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। सम्पूर्ण तहसील समाधान दिवस कार्यक्रम के इस अवसर पर उपरोक्त के अतिरिक्तमुख्य चिकित्सा अधिकारी डा रजत कुमार चौरसिया, पीडी नागेन्द्र मोहन राम त्रिपाठी, डीडीओ राजमणि वर्मा, डीसी मनरेगा सन्दीप सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी वाचस्पति झा, जिला पूर्ति अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह, तहसीलदार नौगढ़, तहसील नौगढ़ क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त थानाध्यक्ष एवं खण्ड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, तथा अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह स्थल की व्यवस्था का डीएम, एसएसपी व पूर्व मंत्री ने किया निरीक्षण

मंत्र भारत संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन द्वारा पूर्व मंत्री व विधायक बांसी जय प्रताप सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा0 अभिषेक महाजन के साथ रतन सेन महाविद्यालय बांसी में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान रतनसेन महाविद्यालय में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान यातायात व्यवस्था, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण, महिला सुरक्षा, वीआईपी आगमन-प्रस्थान मार्ग तथा आपातकालीन निकास व्यवस्था कराये जाने के बारे में सम्बन्धित को निर्देश दिया। इसके अलावा वर-बधू को दी जाने वाले सामानों की सूची का बैनर लगवाने का निर्देश दिया। पीने के पानी व अन्य आवश्यक व्यवस्था कराने का निर्देश् दिया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक डा ज्ञानप्रकाश, उपजिलाधिकारी बांसी निखिल चक्रवर्ती, पीडी नागेन्द्र मोहन राम त्रिपाठी, जिला समाज कल्याण अधिकारी महिपाल सिंह व अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

आगामी त्यौहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सम्भ्रांत व्यक्तियों के साथ पीस कमेटी की बैठक

मंत्र भारत संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र में आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी विवेकानंद मिश्रा व क्षेत्राधिकारी मयंक द्विवेदी ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रहरियों एवं गणमान्य नागरिकों के साथ विस्तृत वार्ता कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक को संबोधित करते हुए उपजिलाधिकारी विवेकानंद मिश्रा ने कहा कि पूर्व वर्षों की भांति इस बार भी होली का पर्व परंपरागत तरीके से ही मनाया जाएगा तथा किसी भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि होलिका दहन पूर्व से चिन्हित एवं प्रस्तावित स्थलों पर ही किया जाएगा। जुलूस निकालने के लिए प्रशासन से विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यदि किसी क्षेत्र में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो प्रशासन द्वारा उसका त्वरित समाधान कराया जाएगा।

वहीं क्षेत्राधिकारी मयंक द्विवेदी ने बताया कि तहसील क्षेत्र में कुल 163 स्थानों पर होलिका दहन प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि होली आपसी भाईचारे और खुशियों का पर्व है। यदि किसी समुदाय का व्यक्ति होली नहीं खेलना चाहता है तो उसके साथ जबरन रंग न खेलें। उन्होंने सभी से सतर्कता बरतने और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।

सीओ ने होली के अवसर पर अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, भंडारण एवं सेवन पर सख्त प्रतिबंध लगाने की बात कही। उन्होंने आश्वस्त किया कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम प्रहरियों को अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बीते वर्ष होली के दिन बाणगंगा बैराज पर हुई दुर्घटना का भी उल्लेख किया गया। प्रशासन ने इस वर्ष एहतियातन होली के दिन बैराज के उत्तर एवं दक्षिण दिशा में नदी में स्नान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। साथ ही बैराज पर प्रकाश व्यवस्था, एनाउंसमेंट और पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने हेतु प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

बैठक में चेयरमैन प्रतिनिधि रवि अग्रवाल, सुधांशु बोरा, सूर्य प्रकाश पाण्डेय, शिव प्रसाद वर्मा, सौरभ गुप्ता, शैलेन्द्र कौशल, मनोज कुमार गुप्ता, महेश कसौधन, दिलीप वर्मा, वीरेन्द्र मोदनवाल, संजय दूबे, निसार अहमद, रोहित मद्धेशिया, अल्ताफ हुसैन, वकील खान, वीरेंद्र प्रताप जायसवाल, रमेश मणि त्रिपाठी, संतोष पासवान, विवेक पाण्डेय, अजय चौधरी, सुभाष यादव, मेजर सिंह चौहान, पिंटू सिंह, बबलू गौड़, प्रमोद श्रीवास्तव, वीरेंद्र गौड़, राजू बाबा, शौकी लाल, राम मिलन चौधरी, ओमप्रकाश यादव, पिंटू पटेल सहित एसडीओ विद्युत विनोद कुमार, लिपिक राजेश त्रिपाठी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।

बाल श्रम और मानव तस्करी के रोकथाम के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक गोष्ठी का आयोजन

मंत्र भारत संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक महाजन के आदेश के क्रम में प्रशान्त कुमार प्रसाद के कुशल निर्देशन में, सुबेन्दु सिंह किशोर पुलिस इकाई के नोडल अधिकारी/क्षेत्राधिकारी अपराध के कुशल पर्यवेक्षण मे, मनोज कुमार श्रीवास्तव प्रभारी निरीक्षक एएचटीयू द्वारा विशेष किशोर पुलिस इकाई की मासिक समीक्षा एव समन्वय गोष्ठी की गयी । जिसमें पूर्व में जारी किए गए कार्यवृत् का अनुपालन के संबंध में चर्चा की गई । उपस्थित अन्य अधिकारी गण द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जारी एसओपी अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/विवेचको के समक्ष आ रही समस्या, एवं सुझाव पीड़ितों के आवासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशा मुक्त अभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैंगिक समानता, नारी शक्ति, किशोर न्याय अधिनियम 2015 मे हुए नवीनतम संशोधन पोस्को को एक्ट के अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के अंदर सीडब्ल्यूसी को सूचित करना, पॉस्को के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरकर संबंधित को समय से भेजा जाना बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य का पालन, जे.जे एक्ट के अंतर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारियों रिमांड लेने हेतु सादे वस्त्रों में आने जे.जे एक्ट की धारा 24 आदि तथा पोक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्तों की माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त बेल नोटिस को बाल कल्याण समिति एवं वादी /पीड़िता को अंदर समय उपलब्ध कराना के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस दौरान जनपद सिद्धार्थनगर के बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, जनपद के समस्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारीगण, एएचटीयू/एसजेपीयू के अधिकारी/कर्मचारीगण, मानव सेवा संस्थान गोरखपुर एनजीओ के कर्मचारीगण, मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान सिद्धार्थनगर के कर्मचारीगण एवं अन्य विभागों के अधिकारी/कर्मचारीगण गण शामिल हुए।

सम्पादकीय

एआइ बदलेगा विकास का भविष्य, दिल्ली समिट से उभरीं संभावनाएं और चुनौतियां

यह एक जगजाहिर तथ्य है कि दुनिया आज तकनीकी विकास के अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसका एक सबसे अहम औजार बनने जा रही है। दिल्ली में आयोजित 'इंडिया-एआइ इम्पैक्ट समिट, 2026' में इस संदर्भ में जितने आयाम सामने आए, वे बताते हैं कि दुनिया भर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआइ केंद्रित बदलाव अब विकास की नई परिभाषा गढ़ने जा रहा है। इसमें भारत की एक अहम भूमिका होगी और खासतौर पर वैश्विक दक्षिण या विकासशील देशों में इसे नेतृत्वकारी भूमिका में देखा जा रहा है।

गौरतलब है कि एआइ का इस्तेमाल अब केवल सुरक्षा के मुद्दे तक केंद्रित नहीं है और आज विकास के क्षेत्र में समावेशी, पारदर्शी तथा जिम्मेदार सुशासन के तौर पर इसकी भूमिका का विस्तार हो रहा है। जहां तक दिल्ली में हुए एआइ सम्मेलन का सवाल है, इसमें स्वास्थ्य, कृषि, जलवायु परिवर्तन, शासन और आर्थिक विकास के मामले में खड़ी होने वाली बाधाओं का हल निकालने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को आगे बढ़ाने की जमीन तैयार करने की कोशिश की गई। यानी सम्मेलन में एआइ के जरिए समग्र विकास के क्षेत्र में संभावनाओं की नई राह तलाशने की भूमिका बनी।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान तकनीक, चिकित्सा और अन्य उत्पादों के निर्माण तथा उपयोग में एआइ का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। विकास के लगभग सभी क्षेत्र में इसकी अहमियत जिस रूप में बनती देखी जा रही है, उसके मद्देनजर भारत ने भी अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन यह भी सच है कि फिलहाल इस क्षेत्र में चीन और अमेरिका की कंपनियों का वर्चस्व है।

निश्चित तौर पर भारत जैसे विकासशील देशों के सामने यह एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी समस्या से पार तभी पाया जा सकता है, जब उसकी जटिलता को स्वीकार कर उसका सामना करने का विकल्प चुन लिया जाए। इस लिहाज से देखा जाए, तो भारत का यह रुख तकनीकी प्रतिस्पर्धा के मैदान में चुनौतियों का सामना करने की जमीन तैयार करता है कि देश एआइ से डरता नहीं है, बल्कि इसमें वैश्विक भलाई के लिए समृद्धि और भविष्य की संभावनाएं देखता है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि एआइ अब भविष्य की दुनिया का एक यथार्थ है और विकास की पटकथा तैयार करने में इसकी अहम भूमिका होने जा रही है। मगर इसके समांतर यह देखने की जरूरत होगी कि नए बनने वाले ढांचे में समाज के सभी वर्गों के हित को सुनिश्चित करने का उद्देश्य किस हद तक पूरा हो पाता है। इस संदर्भ में एआइ की बढ़ती भूमिका के दौर में बड़े पैमाने पर नौकरियों का दायरा सिकुड़ने और अवसर कम होने की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसका हल निकालना एक बड़ी चुनौती होगी।

इसके अलावा, एआइ आधारित तकनीक का बेजा इस्तेमाल करके भयादोहन, डीपफेक से जुड़ी जटिलताएं, डेटा केंद्रों से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव, ज्यादा से ज्यादा डेटा हासिल करके उसका मनमाना उपयोग और उसे नियंत्रण का एक औजार बनाने जैसे सवाल भी सामने खड़े होंगे। इन समस्याओं का हल निकालने पर ही इस तकनीक की साख निर्भर करेगी।

यों दिल्ली के सम्मेलन में एक सकारात्मक उम्मीद यह जताई गई कि एआइ अरबों लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकता है और एक बेहतर दुनिया बना सकता है। मगर यह इस पर निर्भर करेगा कि एआइ की नई दुनिया में वंचित तबकों एवं गरीब आबादी की कितनी पहुंच संभव हो सकेगी और इसका चेहरा कितना मानवीय तथा समावेशी बनाया जा सकेगा।

राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के वर्षपर्यंत सियासी मायने

चिरंजीवी सदन 'राज्यसभा' के द्विवार्षिक चुनाव के लिए वर्ष 2026 में विभिन्न चरणों में खाली होने वाली कुल 71-75 सीटें के लिए चुनाव होंगे, जो पूरे वर्ष अप्रैल और नवंबर में भरी जाएंगी। लिहाजा, इन चुनावों के राजनीतिक मायने गहन व अहम हैं, क्योंकि ये चुनाव जहां एनडीए की बहुमत मजबूती बढ़ा सकते हैं, वहीं विपक्ष को भी कमजोर कर सकते हैं। इससे भाजपा व उसके साथियों का चुनावी हौसला बढ़ेगा।

जहां तक इनकी प्रमुख तारीखों की बात है तो चुनाव आयोग ने पहले चरण में 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव घोषित किए हैं। जिसके लिए अधिसूचना 26 फरवरी को जारी होगी, नामांकन 5 मार्च तक, और मतदान-मतगणना 16 मार्च 2026 को। जबकि बाकी सीटें नवंबर में भरी जाएंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन दस चुनावी राज्यों में से 6 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जबकि 4 राज्यों में इंडी गठबंधन के घटक दल सरकार में हैं। जहां तक राज्यवार सीटों की बात है कि पहले चरण में महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल की 5, बिहार की 5, ओडिशा की 4, असम की 3, हरियाणा की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीटें शामिल हैं, जबकि दूसरे चरण में उत्तरप्रदेश की 10 और झारखंड, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना आदि की 20 से अधिक सीटों के लिए नवम्बर में चुनाव होंगे।

जहां तक उच्च सदन राज्यसभा में वर्तमान दलगत स्थिति की बात है तो राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जहां भाजपा के 103 और एनडीए के 121-129 सांसद हैं। जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पास 78-80 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के 27 सांसद हैं। जहां तक इन चुनावों के राजनीतिक प्रभाव की बात है तो इन चुनावों में एनडीए को 7-9 या इससे अधिक सीटों का लाभ मिलने का अनुमान है, जिससे उनकी संख्या 145 तक पहुंच सकती है। जबकि विपक्ष को 5 सीटें खोने का खतरा, खासकर बिहार, महाराष्ट्र में है। इससे अनुसार, 71-75 खाली सीटों में से एनडीए को नेट 7-9 या 48 सीटें हासिल हो सकती हैं। चूंकि वर्तमान में एनडीए के 121-129 सदस्य हैं, इसलिए चुनाव बाद 145 तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं बाद के जून-नवम्बर वाले दूसरे चरणों के प्रभाव की बात है तो वे भी स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में सीटों से 75 पर सिमट सकता है। कांग्रेस को विशेष रूप से 8 सीटें खोने का खतरा, जिसमें मल्लिकार्जुन खरगे, दिग्विजय सिंह की सीटें भी शामिल हैं। वहीं बाद के चरणों का प्रभाव भी उसपर पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 10 सीटें में से सपा को 2-3 मिलनी संभावित हैं, लेकिन कुल नुकसान

भाजपा को राज्यसभा में अब कोई भी विधेयक पास करना आसान होगा और सुपरमेजॉरिटी की ओर बढ़त भी उसे मिलेगी।

सवाल है कि इन चुनावों में एनडीए को कितनी सीटें मिलने की संभावना है तो राजनीतिक विश्लेषकों को अनुमान है कि एनडीए को 2026 के राज्यसभा चुनावों में कुल 48 या इससे अधिक सीटें मिलने की संभावना है, जिससे उनकी ताकत 129 से बढ़कर 140 हो सकती है। पहले चरण के 37 सीटों पर 5-7 का लाभ अनुमानित है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे बाद के चरणों से भी उसे अतिरिक्त मजबूती मिलेगी। राजनीतिक विश्लेषकों के भाजपा को 7-8 मिलनी संभावित है, जबकि ओडिशा, तेलंगाना आदि में स्थिरतामिलेगी।, कुल मिलाकर सुपरमेजॉरिटी (123) पक्की होगी। जबकि विपक्ष को 5 नुकसान होगा।

जहां तक इन चुनावों में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की बात हैं तो इंडिया गठबंधन को 2026 के राज्यसभा चुनावों में कुल 71-75 सीटों में से नेट 5 का नुकसान हो सकता है, जिससे उनकी संख्या 80 से घटकर 75 रह जाएगी। पहले चरण के 37 सीटों पर भी नुकसान की स्थिति बनी हुई है, हालांकि कुछ राज्यों में स्थिरता संभव है। विश्लेषकों के अनुसार, इंडिया ब्लॉक वर्तमान 80 होगा। जबकि कर्नाटक, झारखंड में 1-1 सीटों का नुकसान संभव है। ओवरऑल, एनडीए के लाभ से इंडिया कमजोर होगा।

जहां तक राज्यवार स्थिति की बात है तो बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होगा। अभी आरजेडी के 2, जेडीयू के 2 और एक सांसद राष्ट्रीय लोक मोर्चा का है। बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा में एक सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए के पास 202 विधायक हैं और एनडीए के खाते में 4 सीटें सुनिश्चित हैं, जबकि 5 के लिए जोर आजमाइश बढ़ेगी। क्योंकि यहां 35 सीटों के साथ I.N.D.I.A. एक भी सीट अपने बल पर जीतने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में 5 विधायकों वाला AIMIM की भूमिका अहम हो जाती है। यदि पूरा विपक्ष एकजुट होता है तो बिहार में विपक्ष के पास कुल 41 विधायक हो जाते हैं और विपक्ष एक सीट निकाल सकते हैं। ऐसे में यह चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व और विपक्षी एकता की के लिए अग्निपरीक्षा होगा।

वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के नेतृत्व में सत्तारूढ़ महायुति आसानी से 6 सीटों पर जीत हासिल कर लेगा, वहीं 7वीं सीट के लिए वोटिंग हो सकती है। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का संसदीय सफर थम सकता है। जबकि हरियाणा से बीजेपी के दो सदस्य किरण चौधरी और रामचंद्र जांगरा का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इसी प्रकार ओडिशा की 4 सीटों पर चुनाव होंगे, जहां अभी 2 सीट बीजेपी और 2 बीजेडी के पास है लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी की सीटों में इजाफा होना तय है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में दोनों सीटें अभी कांग्रेस के पास हैं और यहां भी बीजेपी जीत दर्ज करने की स्थिति में है।

रही बात तेलंगाना की तो वहां से कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी रिटायर हो रहे हैं और बीआरएस के एक कैंडिडेट का कार्यकाल पूरा हो रहा है। तेलंगाना में काग्रेस दोनों सीटें जीत सकती है और हिमाचल में भी काग्रेस एक सीट जीत सकती है। असम से तीन पश्चिम बंगाल से 5 और तमिलनाडु से भी 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। चूंकि इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इन राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टियों के पास राज्यसभा में अपना संख्याबल कायम रखने का मौका मिलेगा।

यही वजह है कि क्रॉस वोटिंग से निपटने की चुनौती विपक्ष के सामने रहेगी। क्योंकि राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के लिए अपने अपने विधायको को एकजुट रखने की चुनौती हमेशा होती है। पिछले कुछ राज्यसभा चुनावों को देखें तो हरियाणा में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का सामना करना पड़ा था। इसलिए आने वाले राज्यसभा चुनावों को देखें तो चाहे हरियाणा हो, बिहार हो, यहां पर काग्रेस और सहयोगी दलों को फूंक-फूंक करकदम रखना होगा। हालांकि कुछ सीटों पर तो रिजल्ट पहले से ही तय है, लेकिन अगर विपक्ष क्रॉस वोटिंग को रोक पाता है तो उसके हाथ भी कुछ सीट आ सकतीहैं। चूंकि राज्यसभा में बीजेपी और एनडीए का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए इस वर्ष 75 सीटों पर होने वाले चुनावों में विपक्ष यदि कारगर रणनीति नहीं बनाता है तो फिर इंडिया गठबंधन वाले कांग्रेस और उसके सहयोगियों की संख्या और घट सकती है, इतना तय है। जहां तक इन चुनावों में प्रमुख नेताओं के प्रभावित होने की बात है तो कई दिग्गजों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के शरद पवार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, जदयू नेता हरिवंश, भाजपा के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी (6 मंत्री सहित) शामिल हैं। वहीं बीएसपी राज्यसभा से साफ हो सकती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा को 7, सपा को 2 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं राजद और बीजद समेत कई दलों की सीटें घटेगी।

आत्मा खोने पर सिर्फ नाम और नंबर की सूची बनकर रह जाएंगे रिश्ते

रिश्ते कभी वसंत की तरह खिलखिलाते हैं, कभी बरसात की तरह गीला-गीला होते हैं, कभी ग्रीष्म की तरह तपते हैं और कभी पतझड़ की तरह सूने-सूने लगते हैं। मगर बीते कुछ दशकों में इनका बदलना सिर्फ स्वाभाविक चक्र नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के गहरे बदलावों का आईना भी बन गया है। आज जब हम चारों ओर देखते हैं, तो पाते हैं कि रिश्तों का रूप, उनकी परिभाषा और उनका निभाया जाना- सब कुछ बदल रहा है। यह स्थिति हमें कभी सुकून देती है, तो कभी बेचैनी से भर देती है।

कभी भारतीय समाज की सबसे बड़ी पहचान संयुक्त परिवार हुआ करती थी। एक ही छत के नीचे तीन-चार पीढ़ियां साथ रहती थीं। बच्चों का पालन-पोषण सिर्फ मां-बाप तक सीमित नहीं था, उसमें दादी-नानी का दुलार, बड़ों की डांट और छोटे-बड़े भाई-बहनों की शरारतें शामिल थीं। त्योहार धार्मिक अवसर मात्र नहीं होते थे, बल्कि वे पारिवारिक एकजुटता और रिश्तों की मजबूती का उत्सव होते थे। अब वही संयुक्त परिवार टूटकर छोटे-छोटे फ्लैटों में सिमट गए हैं। महानगरों की नौकरी और पढ़ाई ने हमें ऐसी जगह पहुंचा दिया है, जहां न तो आंगन है, न चौपाल। चार पीढ़ियों का साथ अब दुर्लभ हो गया है। रिश्तों की नजदीकी धीरे-धीरे दूरी में बदल गई है।

डिजिटल क्रांति ने इस दूरी को और भी गहराई दी है। दोस्त अब मोहल्ले की गली या गांव की चौपाल पर नहीं मिलते, वे सोशल मीडिया और आभासी खेलों की दुनिया में मिलते हैं। भाई-बहन एक ही घर में रहकर भी अपने-अपने डिजिटल कमरों में कैद हैं। किसी के कानों में हेडफोन है, किसी की आंखों पर मोबाइल की स्क्रीन चमक रही है। माता-पिता के पास बच्चों से बात करने का समय नहीं और बच्चों के पास माता-पिता को सुनने का धैर्य नहीं। संवाद जो कभी रिश्तों की जान हुआ करता था, अब सोशल मीडिया के अलग-अलग मंचों पर 'स्टेटस अपडेट' की दुनिया में बिखर गया है। शिकायतें सीधे कहे जाने के बजाय इशारों और 'इमोजी' में बदल गई हैं।

यह भी सच है कि डिजिटल दुनिया ने कुछ नए रास्ते खोले हैं। परदेस गया बेटा अब अपनी मां से रोज वीडियो काल के जरिए बात कर सकता है। बहन-भाई रक्षाबंधन पर आनलाइन तोहफे भेज सकते हैं। विदेश में बैठा छात्र अपने गांव की शादी का सीधा प्रसारण देख सकता है। यह सब तकनीक की देन है और रिश्तों को नई तरह की निकटता भी देती है। मगर सवाल यही है कि क्या यह निकटता असली अपनापन बन पाती है? दिल का 'इमोजी' क्या सचमुच धड़कते दिल की गर्माहट पहुंचा सकता है? एक वीडियो काल क्या मां की गोद का विकल्प हो सकता है?

नई पीढ़ी रिश्तों को बराबरी की नजर से देखती है। बेटियां अपने फैसले खुद ले रही हैं, बेटे घर के कामों में हाथ बंटा रहे हैं। विवाह और दोस्ती, दोनों में बराबरी का भाव बढ़ा है। जाति और धर्म के बंधनों को भी धीरे-धीरे चुनौती दी जा रही है। यह बदलाव सकारात्मक है, क्योंकि यह रिश्तों को न्यायपूर्ण और अधिक मानवीय बना रहा है। मगर साथ ही यह पीढ़ी धैर्य और प्रतीक्षा से भी दूर जा रही है। हर चीज उन्हें तुरंत चाहिए- खाना, प्यार और रिश्ते भी। यही कारण है कि अब टूटते रिश्ते किसी को ज्यादा विचलित नहीं करते। सोशल मीडिया पर 'ब्लाक' और 'अनफ्रेंड' रिश्तों को खत्म करने का सबसे आसान रास्ता बन गए हैं। जहां पहले रिश्ते निभाने के लिए समझौते और त्याग की जरूरत होती थी, वहां अब एक क्लिक से रिश्ता खत्म करना आम हो गया है।

उपभोक्तावादी संस्कृति ने भी रिश्तों की आत्मा को गहराई से प्रभावित किया है। पहले रिश्ते अपनापन और जिम्मेदारी के आधार पर चलते थे। अब वे लाभ-हानि के तराजू में तौले जाने लगे हैं। दोस्ती तब तक है, जब तक काम आ रही है। विवाह तब तक है, जब तक सुख और सुविधा मिल रही है। पड़ोस तब तक है, जब तक उससे कोई फायदा जुड़ा हुआ है। यह मानसिकता रिश्तों को खोखला कर रही है। रिश्ते अब जिम्मेदारी कम और सौदेबाजी ज्यादा लगने लगे हैं।

त्योहारों की दुनिया में भी यही बदलाव दिखता है। पहले दीपावली पर घर-घर जाकर मिठाइयां बांटी जाती थीं, अब आनलाइन तोहफे का 'वाउचर' भेजना काफी समझा जाता है। होली पर गले मिलने की जगह 'हैप्पी होली' का संदेश भेज देना सामान्य हो गया है। ईद की सेवई और क्रिसमस का केक अब 'वाट्सएप स्टिकर' तक सिमट गया है। त्योहारों की आत्मा रिश्तों की गहराई थी, जो अब बाजार और तकनीक की चमक में कहीं खोती जा रही है।

फिर भी तस्वीर पूरी तरह अंधेरी नहीं है। बदलते रिश्तों के इस मौसम ने नई संभावनाएं भी खोली हैं। अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों की स्वीकृति बढ़ रही है। दूरदराज के रिश्तेदार मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए लगातार जुड़े रह सकते हैं। मगर मूल सवाल वही है कि क्या यह सब रिश्तों को जीवित रखने के लिए काफी है? क्या आभासी अपनापन वास्तविक संवेदना की जगह ले सकता है? सच तो यही है कि रिश्ते निभाने के लिए तकनीक से अधिक संवेदना चाहिए। उन्हें जीवित रखने के लिए समय चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बढ़कर वह मानवीय स्पर्श चाहिए, जिसे कोई मशीन नहीं दे सकती।

रिश्तों का मौसम चाहे जैसे भी बदले, उनकी आत्मा वही पुरानी है- विश्वास, अपनापन और जिम्मेदारी। अगर आत्मा बची रही तो रिश्ते बदलते मौसमों में भी हरे-भरे रहेंगे। अगर यह आत्मा खो गई, तो रिश्ते सिर्फ नामों और नंबरों की सूची बनकर रह जाएंगे। आज हमें यही तय करना है कि हम किस मौसम में जीना चाहते हैं- वसंत की गुनगुनाती गरमाहट में या पतझड़ की सूनी उदासी में।

हाल ही में तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कराईकुडी में अपनी जड़ों से जुड़े रहने की एक घटना चर्चा में आई। यहां एक ही परिवार की पीढ़ियों ने गांव-घर लौटने का मन बनाया। दुनिया के अलग-अलग हिस्से में जा बसे इन लोगों ने व्यस्तता और जीवन की आपाधापी को भूल कर एक-दूजे से मिलने का मार्ग निकाला और अपने पैतृक आवास पर पहुंच गए। बिखरते रिश्तों के इस दौर में यह प्रयास पीढ़ियों को जोड़ने की एक प्रेरणादायी घटना है।

लक्ष्य से दूर कार्बन उत्सर्जन पर लगाम, भारत की अपनी चिंताएं और चुनौतियां

धरती का तापमान न बढ़े, इसके लिए कवायद तो हो रही है, लेकिन दुनिया भर के देशों की वर्तमान नीतियां ऐसी हैं जो तापमान को 2.3 से 2.5 डिग्री तक ले जा सकती हैं। हालांकि कई देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिया है। फिर भी 29 देशों में कार्बन उत्सर्जन उच्च स्तर पर बना हुआ है। दूसरी ओर, भारत कम उत्सर्जन के साथ मध्यम प्रदर्शन कर रहा है।

'कार्बन मार्केट वाच' की रपट बताती है कि वर्तमान समय में विश्व के कई बड़े देश जलवायु परिवर्तन रोकने में सफल नहीं रहे हैं। लिहाजा 1.5 डिग्री तापमान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्बन उत्सर्जन में 43 फीसद कमी लाने की जरूरत है। मगर इसकी उम्मीद अभी नहीं दिख रही है। कई बड़े उद्योगों का कामकाज जलवायु लक्ष्यों के अनुकूल नहीं है। सच यह है कि वैश्विक तापमान बढ़ने से रोकने के प्रयास अपर्याप्त हैं।

पिछले जी-20 सम्मेलन में शामिल देशों में वर्ष 2050 तक पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी को डेढ़ डिग्री तक रखने पर सहमति बनी थी। यह अच्छी बात है कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देता है। मगर यह भी सच है कि भारत के विकास लक्ष्यों के साथ जलवायु अनुकूलन का तालमेल स्थापित करने में कहीं न कहीं कमी रह जाती है।

गौरतलब है कि वर्ष 2022 में भारत ने कई महीनों तक गर्म हवाओं, बाढ़ और चक्रवात जैसी विषम मौसमी घटनाओं का सामना किया था, जिससे जन-जीवन से लेकर लोगों की आजीविका तक प्रभावित हुई। साथ ही विकास कार्यों के लिए यह स्थिति बाधा बनी रही।

'नेट जीरो' का मतलब ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य करना भर नहीं है, बल्कि इन गैसों को दूसरे कामों से संतुलित करना भी है। ऐसी अर्थव्यवस्था भी तैयार करना है, जिसमें जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल न के बराबर हो। साथ ही कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीजों का इस्तेमाल भी कम से कम हो। अभी जितना कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है, उसी के अनुपात में उसे अवशोषित करने का भी इंतजाम हो।

यह पर्यावरण संरक्षण से ही संभव है। यदि कार्बन उत्सर्जन एक निश्चित मात्रा में होता है और उत्सर्जन करने वाली इकाई उसी अनुपात में पेड़ों को महत्त्व देती है, तो कार्बन उत्सर्जन और अवशोषण की समानता के कारण उत्सर्जन को शून्य स्तर पर ले जाना आसान हो जाएगा। मगर मौजूदा दौर में जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे अब शून्य उत्सर्जन के बारे में सोचना सपना ही लगता है। फिलहाल दुनिया में केवल दो देश भूटान और सूरीनाम ही हैं, जहां कार्बन उत्सर्जन शून्य है। इसकी वजह वहां कम आबादी और चारों तरफ हरियाली है।

महज वादे करने और इरादे जताने भर से इस उत्सर्जन को शून्य पर लाना संभव नहीं है। छोटे-बड़े कई देशों ने संकल्प तो जताया, लेकिन उत्सर्जन रोकने के के ठोस उपाय नहीं किए। नतीजा अब पूरी दुनिया देख रही है। अगर ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन इसी तरह होता रहा, तो वर्ष 2050 तक पृथ्वी का तापमान दो डिग्री बढ़ जाएगा। यह पूरी दुनिया के लिए भयावह होगा। लोगों को भीषण सूखा से लेकर विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। हिमखंड और अधिक पिघलेंगे। समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। ऐसे में कई देशों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा होगा।

दुनिया के 192 देश संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का हिस्सा हैं। इनमें 137 देश शून्य उत्सर्जन का समर्थन करते हैं। देखा जाए, तो कुल ग्रीनहाउस उत्सर्जन में इनकी हिस्सेदारी 80 फीसद है। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले चीन और अमेरिका भी इसी में शामिल हैं। चीन ने वर्ष 2026 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, लेकिन इस मामले में वह कितना खरा उतरेगा, कहना मुश्किल है। दूसरी ओर, जर्मनी और स्वीडन जैसे देश 2045 तक, जबकि आस्ट्रिया, फिनलैंड और उरूग्वे ने अलग-अलग समय में शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।

अमेरिका के अलावा ऐसे कई देश हैं जो इस मामले में कहीं आगे जाकर वर्ष 2050 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखते हैं। इस बीच सुखद यह है कि जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती के बीच भारत के वन क्षेत्र में वर्ष 2021 के दौरान तीन फीसद से अधिक बढ़ोतरी हुई। वैसे भारत जलवायु परिवर्तन को लेकर दूसरे देशों के मुकाबले कहीं अधिक चिंतित है। इस समय वह नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष जोर दे रहा है।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (काप-26) में भारत ने इस मामले में अपना पक्ष रखा था। अभी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा को किसी भी तरह कम किया जाए। दूसरा यह कि अपनी 50 फीसद ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा से कैसे पूरा किया जाए। वहीं कार्बन उत्सर्जन को भी कम करते जाना है।

इसके अलावा, वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य तो है ही। हालांकि समय की कसौटी पर कौन कितना खरा उतरेगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है, यह अब पूरी दुनिया में दिखने लगा है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में हरित विकास पर जोर दिया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी बनाना और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।

बजट में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भी बड़ी राशि आबंटित की गई है और ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रानिक वाहनों तथा परमाणु ऊर्जा के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। इस वर्ष के बजट में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने की पहल दिखती है। हरित ऊर्जा गलियारा, परमाणु ऊर्जा पर जोर और हरित बुनियादी ढांचा- ये सब ऐसे संदर्भ हैं, जिस पर भारत 'पृथ्वी प्रथम' की नीति को महत्त्व देता है। जबकि कुछ ताकतवर देश अपनी नीतियों में 'देश प्रथम' को महत्त्व दे रहे हैं। नतीजा यह कि इसकी कीमत शेष देश चुका रहे हैं।

दुनिया भर के देश अगर किसी भी तरह जल्दी अथवा धीरे-धीरे ही सही कार्बन उत्सर्जन कम करने का संकल्प करें, तो न केवल पृथ्वी, बल्कि पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। यह निराशाजनक ही है कि कार्बन उत्सर्जन पर लगाम के मुद्दे पर दुनिया के देशों में कागजी एकजुटता तो देखने को मिलती है, लेकिन जमीनी स्तर पर वे सार्थक पहल करते नहीं दिखते। वहीं विकसित और विकासशील देशों के बीच नाहक ही इस मुद्दे पर आरोप-प्रत्यारोप चलता रहता है। सभी को सोचना होगा कि भौगोलिक सीमाओं में बेशक सभी देश बंटे हुए हैं, लेकिन धरती तो एक ही है और सभी को मिल कर उसे बचाना है। दुनिया को यह सोचना पड़ेगा कि 'राष्ट्र प्रथम' की नीति लेकर नहीं, बल्कि वैश्विक सुशासन के साथ काम करना होगा।

फिलहाल भारत की अपनी चिंताएं और चुनौतियां हैं। अगर यह का बन उत्सर्जन पर सख्ती से कदम उठाता है, तो इसके दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं। सच भी है कि अन्य विकसित और विकासशील देशों की तुलना में भारत कार्बन उत्सर्जन के मामले में संयमित देश है और यह अपने संकल्प को पूरा करने की कोशिश करता है।

पश्चिमी राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बड़ी संख्या में राज्य वृक्ष 'खेजड़ी' को काटे जाने और गांवों की चरागाह भूमि के अधिग्रहण का व्यापक स्तर पर विरोध होना कोई सामान्य घटना नहीं है। स्थानीय लोगों की ओर से इन दरख्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पारंपरिक चरागाहों के संरक्षण की मांग ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि जिस सौर ऊर्जा को पर्यावरण हितैषी माना जाता है, क्या उसी के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना उचित है?

अग्निवीर धीरज गुप्ता को नम आंखों से अंतिम विदाई

अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। औराई क्षेत्र के जेठूपुर गांव निवासी अग्निवीर धीरज गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु से पूरे जनपद में शोक की लहर है। जम्मू-कश्मीर के नगरोटा में तैनात धीरज का पार्थिव शरीर सैन्य वाहन से वाराणसी स्थित मिलिट्री कैंप लाया गया, जहां सैन्य अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शनिवार सुबह तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर जनपद पहुंचते ही बाबूसराय, औराई और घोसिया में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में तिरंगा लिए लोग अपने वीर सपूत के अंतिम दर्शन को सड़कों पर खड़े रहे। 'अग्निवीर धीरज गुप्ता अमर रहें' के नारों से वातावरण गूंज उठा और हर आंख नम दिखी।

जिलाधिकारी शैलेष कुमार पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक सहित जनप्रतिनिधियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भोगांव गंगा घाट पर सैन्य सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ।

धीरज की असामयिक मृत्यु से क्षेत्र स्तब्ध है। अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब उनके प्रति लोगों के प्रेम, सम्मान और देशभक्ति की भावना को दर्शाता रहा।

सीएम डैशबोर्ड में जनपद की रैंकिंग सुधार को लेकर सीडीओ की अध्यक्षता में विकास कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित प्राप्तांक एवं ग्रेडिंग के आधार पर विकास कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा सहित निर्माणाधीन निर्मित 85 इंडिकेटर्स की समीक्षा जिलाधिकारी शैलेष कुमार के कुशल निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविन्द शुक्ल की अध्यक्षता में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।

इस अवसर पर ने विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों के सतत् प्रयास से माह जनवरी में जनपद के रैंकिंग 15वें स्थान आने पर अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिया कि रैंकिंग में सुधार लाये। जनपद की निर्माणाधीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का मुख्य विकास अधिकारी द्वारा समीक्षा की गयी। जिसमें सभी कार्य को समय के साथ गुणवत्तापूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्हें शीघ्र पूर्ण कर मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर अंकित किया जाय। जिससे जनपद की रैंकिंग में सुधार हा सके। उद्योग विभाग को टूलकिट

वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिये। मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित सभी सूचनाएं समयबद्ध व शत्-प्रतिशत अद्यतन रहनी चाहिए। शासन की प्राथमिक योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नही की जायेगी।

मुख्य विकास अधिकारी ने सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने विभागों में कोई नई परियोजना आ रही है तो डीएसटीओ के माध्यम से जिला प्रशासन से अवलोकित अवश्य कराकर कार्य प्रारम्भ करें। साथ ही सम्बन्धित जॉच अधिकारियों को निर्देश दिया कि मौके पर जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य का डाईग चार्ट, स्टीमेट, कार्य प्रोवेजन सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से अवश्य प्राप्त कर ली जाय। उसी के अनुसार कार्य सुनिश्चित कराये। विलम्बित होने वाली कार्यो पर मुख्य विकास अधिकारी ने गहरी नाराजगी जताते हुए सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय-सीमा के भीतर मानक गुणवत्ता के अनुरूप कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित कराये। इस कार्य में लापरवाही, शिथिलता कत्तई बर्दाश्त नही की जायेगी।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ संतोष चक, जिला विकास अधिकारी ज्ञान प्रकाश, उप कृषि निदेशक अश्वनी सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवम पाण्डेय, नीरव सिंह, सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

आगामी पर्वों को लेकर सुरियावां थाने में पीस कमेटी की बैठक, सौहार्दपूर्ण की अपील

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। होली, ईद-उल-फितर, नवरात्रि व रामनवमी सहित आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से थाना सुरियावां परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई।

बैठक क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार मिश्रा, तहसीलदार भदोही एवं थानाध्यक्ष सुरियावां की मौजूदगी में विभिन्न समुदायों के धर्मगुरुओं, गणमान्य व्यक्तियों, ग्राम प्रधानों व डिजिटल वॉलंटियरों ने भाग लिया।

अधिकारियों ने उपस्थित लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और सुझाव लिए। सभी से अपील की गई कि त्योहारों को आपसी भाईचारे व सौहार्द के साथ मनाएं तथा शासन की गाइडलाइन का पालन करें। बिना अनुमति शोभायात्रा या धार्मिक जुलूस न निकालने और सड़क बाधित कर आयोजन न करने की हिदायत दी गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आमजन से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

जनपद की सभी तहसीलों में आयोजित हुआ सम्पूर्ण समाधान दिवस

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जन शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के उद्देश्य से शनिवार को जनपद की सभी तहसीलों में 'सम्पूर्ण समाधान दिवस' का आयोजन किया गया। तहसील औराई में जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक एवं अन्य अधिकारियों के साथ फरियादियों की समस्याएं सुनीं। कुल 47 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 9 मामलों में तत्काल संयुक्त टीम को स्थलीय निरीक्षण हेतु भेजकर मौके पर निस्तारण कराया गया। शेष मामलों के लिए समय-सीमा निर्धारित करते हुए राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता से संवाद, स्थल निरीक्षण और गुणवत्तापूर्ण आख्या के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी।

तहसील ज्ञानपुर में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) विजय नारायण सिंह व उपजिलाधिकारी भान सिंह, जबकि तहसील भदोही में उपजिलाधिकारी अरुण गिरि सहित अन्य अधिकारियों ने भी समाधान दिवस में जनसमस्याएं सुनीं।

इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा शिविर लगाकर आयुष्मान गोल्डन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, मिशन शक्ति, परिवार नियोजन, बाल विकास एवं राजस्व हेल्प डेस्क के माध्यम से आमजन को योजनाओं की जानकारी व लाभ प्रदान किया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप तहसील स्तर पर ही शिकायतों का प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को उच्च स्तर पर शिकायत करने की आवश्यकता न पड़े। सम्पूर्ण समाधान दिवस सुशासन की दिशा में एक प्रभावी मंच है, जहां अंतरविभागीय समन्वय से त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाता है।

बोर्ड परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न नकल का कोई मामला नहीं

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। जनपद में 21 फरवरी शनिवार को आयोजित बोर्ड परीक्षा की प्रथम व द्वितीय पाली शांतिपूर्वक संपन्न हुई। किसी भी परीक्षा केंद्र से नकल या अनुचित साधनों के प्रयोग की सूचना नहीं मिली।

प्रथम पाली में हाईस्कूल गृह विज्ञान विषय में 7, 371 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें 6, 997 उपस्थित व 374 अनुपस्थित रहे। इंटरमीडिएट व्यवसायिक प्रश्नपत्र में 306 पंजीकृत छात्रों में से 291 उपस्थित और 15 अनुपस्थित रहे। वहीं संस्कृत बोर्ड की पूर्व मध्यमा हिंदी परीक्षा में 286 परीक्षार्थियों में से 193 उपस्थित व 93 अनुपस्थित रहे। द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट इतिहास विषय में 4, 101 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें 3, 825 उपस्थित व 276 अनुपस्थित रहे।

प्रशासन की सतर्कता और कड़ी निगरानी के बीच सभी परीक्षाएं निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गईं। अधिकारियों के अनुसार केंद्रों पर सुरक्षा एवं निरीक्षण व्यवस्था प्रभावी रही।

आज आएंगे प्रभारी मंत्री

भदोही। जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश सरकार में नगर विकास सहित अन्य विभागों के मंत्री ए.के. शर्मा आज 22 फरवरी को शाम 4 बजे भदोही पहुंचेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह सड़क मार्ग से जनपद आगमन के बाद कलेक्ट्रेट ज्ञानपुर में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेंगे।प्रभारी मंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बीएड छात्रों का चित्रकूट भ्रमण समावेशी शिक्षा मॉडल का किया अध्ययन

मंत्र भारत संवाददाता

ज्ञानपुर। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बीएड तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं ने शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत चित्रकूट का दौरा कर शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अनुभव प्राप्त किया।

भ्रमण की शुरुआत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) से हुई, जहां डॉ. अखिलेश पांडेय के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने संस्थान की संरचना, कार्यप्रणाली एवं शैक्षिक अवधारणाओं को विस्तार से समझा। इसके उपरांत छात्र-छात्राएं जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां प्रोफेसर रीना पांडे के नेतृत्व में विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण कराया गया तथा डॉ. नीतू मिश्र एवं डॉ. संध्या पांडेय ने प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं

का समाधान किया। कार्यक्रम में डीन डॉ. निहार रंजन मिश्र, हेड (सामान्य) डॉ. नीतू मिश्र, हेड (विकलांग) डॉ. मुकुल पाण्डेय, डॉ. विश्वेष पाण्डेय, ललित कला विभाग के हेड एवं डीन डॉ. गुलाबधर सहित अन्य प्राध्यापक उपस्थित रहे।

भ्रमण दल को महाविद्यालय से डॉ. अभिमन्यु यादव, डॉ. विपुल यादव एवं डॉ. राममूर्ति बिंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ में डॉ. जयप्रकाश शर्मा, डॉ. लोकपति त्रिपाठी, डॉ. संजय कुमार चौबे, डॉ. सुधीर कुमार रंजन, डॉ. मोनिका, डॉ. जय सिंह यादव, डॉ. लता, डॉ. राजेश यादव, डॉ. अभिषेक एवं राजेश जी भी शामिल रहे। शैक्षिक गतिविधियों के साथ विद्यार्थियों ने गुप्त गोदावरी, कामतानाथ मंदिर तथा रामघाट स्थित मतगजेंद्र मंदिर में दर्शन कर आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त किया।

अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही एवं पुलिस के जवानों द्वारा मार्च 2023 में अग्निवीर के रूप में चयनित होकर भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में बीती रात्रि में देश की सेवा/सुरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त करने वाले शहीद धीरज कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्यामसुंदर गुप्ता निवासी ग्राम जेठूपुर भवानीपुर थाना औराई जनपद भदोही के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर 'गार्ड ऑफ ऑनर' देकर 'शोक शस्त्र' के साथ अंतिम सलामी देकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

710 से सीधे 60420 पहुँचा बिजली का बिल एक महीने से चक्कर काट रहा बुजुर्ग

मीटर रीडर और बिजली विभाग की लापरवाही का नतीजा, बिजली बिल सुधार और कार्यवाही की मांग

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। अभोली ब्लॉक के पाली विद्युत उपकेंद्र से जुड़े मतेथू गांव में बिजली विभाग की लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मीटर रीडर और जिम्मेदार अधिकारियों की कथित अनदेखी के चलते एक उपभोक्ता को स्टोर मीटर रीडिंग के नाम पर एक ही महीने में लगभग 60420 हजार रुपये का भारी-भरकम बिजली बिल थमा दिया गया।

मामला पाली विद्युत उपकेंद्र से जुड़ा है। गांव निवासी 75 वर्षीय रमाशंकर दुबे के अनुसार अगस्त महीने में उनका बिजली बिल मात्र 710 रुपये था, जबकि सितंबर में अचानक बिल बढ़कर करीब 61 हजार रुपये पहुंच गया। भारी बिल देखकर वह हैरान रह गए और तत्काल पावर हाउस पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

पीड़ित का आरोप है कि पिछले एक महीने से वह विभागीय अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। विभागीय कर्मचारियों ने मीटर के 'स्टोर' हो जाने को बिल बढ़ने का कारण बताया, मगर उपभोक्ता का कहना है कि यदि मीटर स्टोर था तो समय रहते इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई।

रमाशंकर दुबे का कहना है कि जब बिल 5-10 हजार रुपये तक पहुंचा था, तब भी विभाग सूचना देकर समस्या का समाधान कर सकता था, लेकिन 60 हजार रुपये का बिल भेजे जाने के बाद जानकारी देना विभागीय लापरवाही को दर्शाता है। इस पूरे मामले में मीटर रीडर और संबंधित जेई की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि ट्विटर पर शिकायत करने के बावजूद फर्जी निस्तारण दिखाकर मामले को बंद कर दिया गया। उन्होंने जिलाधिकारी और योगी आदित्यनाथ सहित विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों से मामले में हस्तक्षेप कर बिल संशोधन और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

डीएम ने तहसील औराई परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों, पटलों व न्यायालयों का किया सघन निरीक्षण

साफ-सफाई, अभिलेख प्रबंधन, लम्बित वादों के निस्तारण व प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश - जिलाधिकारी

मंत्र भारत संवाददाता

भदोही। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट, तहसील एवं विकास खंडों का रोस्टर तैयार कर निरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त क्रम में जिलाधिकारी शैलेष कुमार द्वारा उप जिलाधिकारी औराई न्यायिक आकाश कुमार के साथ तहसील औराई परिसर में स्थित समस्त कार्यालयों, पटलों एवं न्यायालयों का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा पूरे तहसील परिसर का भ्रमण किया गया। निरीक्षण के दौरान तहसील परिसर भदोही में स्थित अनावासीय भवनो में साफ-सफाई की स्थिति एवं जन सामान्य के लिये बैठने / पूछताछ कक्ष / स्वागत कक्ष, पेय जल, जन प्रसाधन, वाहन पार्किंग आदि की समुचित व्यवस्था व तहसील हवालात की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया गया।

राजस्व न्यायालय-मानक के अनुसार एवं निस्तारण हेतु नियत अवधि में पीठासीन अधिकारी द्वारा वादों के निस्तारण की स्थिति, सबसें पुरानें तीन लबित वादों की पत्रावलियों की समीक्षा, -05 वर्ष से पुराने वादों के लंबित होने / निस्तारण की स्थिति, निर्णीत वाद पत्रावलियों के दाखिल दफ्तर किये जाने की स्थिति, अपील / निगरानी हेतु प्राप्त माँग पत्र के सापेक्ष सम्बन्धित न्यायालयों को वाद पत्रावली प्रेषण की स्थिति का अवलोकन किया गया। राजस्व संग्रह -मानक के अनुरुप वसूली की स्थिति, वसूली प्रमाण पत्रों की कम्प्यूटराईजेशन की स्थिति, दो लाख-से-बड़े वसूली-प्रमाण-पत्रों में वसूली की स्थिति, न्यायालय के आदेश से स्थगित / किश्त में जमा होने से सम्बन्धित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति, आगामी दों वित्तीय वर्षों में सेवा निवृत्त होने वाले समस्त कर्मचारियों व लंम्बित पेन्शन प्रकरणों की स्थिति, संग्रह अभिलेखागार में अभिलेखों के रखरखाव, सफाई, प्रकाश, अग्नि शमन यन्त्रों व कीटनाशक छिड़काव की स्थिति, संग्रह कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों जी0पी0एफ0/एन0पी0एस0 पासबुक, चरित्र पंजिकाओं के संरक्षण एवं इन्द्राज़ आदि की अद्यावधिक स्थिति, लम्बित विभागीय कार्यवाही की स्थिति, आडिट आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति का निरीक्षण किया गया।

नजारत-रजिस्टर नं0-4 में अवशेष पड़ी हुई धनराशि के निस्तारण एवं अग्रिम के समायोजन की स्थिति, रजिस्टर नं0-9 (प्रयोक्ता प्रभार मद) में जमा धनराशि को भारतीय स्टेट बैंक के सुरभिः खाता में जमा कराने की स्थिति, डेड स्टाक रजिस्टर का सत्यापन व निषपयोज्य वस्तुओं/अभिलेखों के निस्तारण की स्थिति का अवलोकन किया।

आगामी दों वित्तीय वर्षों में सेवा निवृत्त होने वाले समस्त कर्मचारियों व लम्बित पेन्शन प्रकरणों की स्थिति, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों जी0पी0एफ0/एन0पी0एस0 पासबुक, चरित्र पंजिकाओं के संरक्षण एवं इन्द्राज आदि की अद्यावधिक स्थिति, लम्बित विभागीय कार्यवाही की स्थिति, राजस्य वादों के इश्तहारों के तामीला की स्थिति, आडिट आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति का भी निरीक्षण किया गया।

रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय -भू-लेख अभिलेखागार में सफाई, प्रकाश, अग्नि शमन यन्त्रों व कीटनाशक छिड़काव की स्थिति, समस्त राजस्व ग्रामों के शजरों व जिल्द बन्दोवस्तों की उपलब्धता एवं उनके रख-रखाव की स्थिति, नियत स्थान पर बस्तों को रखने की स्थिति तथा उनमें सम्बन्धित ग्राम के समस्त अभिलेखों की उपलब्धता की स्थिति, -रोस्टर के अनुसार नई खतौनियाँ तैयार करने की स्थिति, रियल टाइम खतौनी तैयार करने की प्रगति, निर्विवाद वरासत में दर्ज वरासतों तथा आर0-6 में अंकित आदेशों को कम्प्यूटर (भूलेख सर्वर) में फीड किये जाने की स्थिति, आर0-6 में अंकिंत आदेशों को कम्प्यूटर में फीड करने के उपरान्त सम्बन्धित आदेश की पर्ची का

लेखपालों को विवरण एवं खतौनी में उसके चस्पा होने की स्थिति, समस्त आर0के0 के मध्य कार्य विभाजन की स्पष्टता की स्थिति, सार्वजनिक प्रयोजन की भूमियों यथा तालाब, पोखर, चकरोड, खलिहान, शमशान आदि पर से अवैध कब्जो को हटाने की स्थिति, विभिन्न प्रयोजनों हेतु भूमि आवंटन, आवंटियों के कब्जा दखल, आवंटन रजिस्टर के रख रखाव की स्थिति, आगामी दों वित्तीय वर्षों में सेवा निवृत्त होंने वाले समस्तं कर्मचारियों व लम्बित पेन्शन प्रकरणों की स्थिति, लेखपालों के सेंवा अभिलेखों जी0पी0एफ0/एन0पी0एस0 पासबुक, चरित्र पंजिकाओं के संरक्षण एवं इन्द्राज आदि की अद्यावधिक स्थिति, लम्बित विभागीय कार्यवाही की स्थिति, तहसील में स्वामित्व योजना की प्रगति का अवलोकन किया गया।

सम्पूर्ण समाधान दिवस, आई0जी0आर0एस0 च प्रमाणपत्रों की समीक्षा-निर्धारित अवधि से अधिक अवधि तक शिकायतें लम्बित रहने के कारणों की समीक्षा, प्राप्त शिकायतों के निस्तारण का मानक के अनुसार दूरभाष अथवा स्थलीय सत्यापन की स्थिति., -निस्तारण आख्या प्राप्त होने पर उप जिलाधिकारी द्वारा अवलोकन कर वेबसाइट पर दर्ज करने / ग्रेडिंग करने की स्थित, जातिः निवास प्रमाण पत्रों के जारी होने की स्थिति, स्वामित्व योजना के अन्तर्गत घरौनी तैयार करने की प्रगति, मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के कियान्वयन की स्थिति। विभागीय कार्यवाहियों/अभियोजन स्वीकृति की स्थिति, प्रभारी अधिकारियों द्वारा रोस्टर के अनुसार, पटलों के निरीक्षण व अनुपालन की स्थिति, राजकीय आस्थान, शत्रु सम्पत्ति व निष्कान्त सम्पत्ति का विवरण व व्यवस्थापन की स्थिति, राजस्व परिषद के पोर्टल पर लेखपाल हल्का सही होने की स्थिति, आडिट आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति।

उप जिलाधिकारी न्यायालय व कार्यालय के निरीक्षण में राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति (धारा-24 एल0आर0एक्ट / धारा 116 राजस्व संहिता, 2006/धारा-40 राजस्व संहिता/निवेश मित्र पोर्टल पर नियत समय सीमा में निस्तारण), निस्तारित वादों के आदेशों को आर0सी0सी0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड किंयें जानें की स्थितिं।5 वर्ष से पुराने वादों के लंबित होने / निस्तारण की स्थिति, फौजदारी वादों का निस्तारण, निर्णीत वाद पत्रावलियों के दाखिल दफ्तर किये जाने की स्थिति, अपील/निगरानीं हेतु प्राप्त माँग पत्र के सापेक्ष सम्बन्धित न्यायालयों को वाद पत्रावली प्रेषण की. स्थिति।

विविध प्रशासनिक कार्य-प्रातः 10से 12 बजे तक जन सुनवाई में नियमित रुप से बैठने तथा उक्त अवधि में प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर सुनवाई करते हुये समस्याओं के निराकरण की स्थिति, उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/ नायब तहसीलदार के तहसील मुख्यालय पर निवासित होने की स्थिति आदि बिंदुओं का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी, तहसीलदार सुनील कुमार, नायाब तहसीलदार, राजस्व कर्मी आदि उपस्थित रहे।

भाजपा नेता की हत्या! दूल्हे के जीजा ने भाजपा नेता के सीने में उतारी गोली, शादी की खुशियां मातम में बदली

सहारनपुर **(एजेंसी)**। कोतवाली मंडी क्षेत्र के गोशाला रोड स्थित रामलीला भवन में एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग ने खुशियों को मातम में बदल दिया। गोली लगने से भाजपा के मानकमऊ मंडल महामंत्री शिवचरण रोहिला (50) की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के बेटे ने इसे साजिश के तहत हत्या बताते हुए आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है।

पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार रात शिवचरण रोहिला नवीन उपाध्याय के बेटे की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। समारोह के दौरान डीजे पर डांस चल रहा था। इसी बीच नवीन उपाध्याय के रिश्तेदार रोहित उपाध्याय (निवासी सरस्वती विहार, थानाभवन, जिला शामली) हाथ में पिस्टल लेकर डांस कर रहा था। तभी फायरिंग हुई और एक गोली शिवचरण रोहिला के सीने में जा लगी।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, समारोह में दो बार हवाई फायरिंग होने की चर्चा है, जिसका डीजे की तेज आवाज के कारण तत्काल पता नहीं चल सका। तीसरी गोली शिवचरण रोहिला को लगी। इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि हवाई फायरिंग के दौरान गोली सीधे सीने में कैसे लगी। पुलिस इन सभी बिंदुओं की जांच कर रही है।

गोली लगते ही समारोह में अफरा-तफरी मच गई। परिजन और अन्य लोग शिवचरण रोहिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतक के बेटे हर्षित रोहिला ने कोतवाली मंडी में तहरीर देकर आरोपी रोहित उपाध्याय पर जानबूझकर और साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि नवीन उपाध्याय उनके पिता के परिचित हैं। हर्षित के अनुसार, उनके पिता गार्डों की नौकरी लगवाने का काम करते थे और भाजपा में मानकमऊ मंडल के महामंत्री पद पर कार्यरत थे।

घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी अभिनंदन सिंह, एसपी सिटी व्योम बिंदल और एएसपी मनोज कुमार यादव मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी रोहित उपाध्याय को बाबा लालदास मंदिर गेट के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से लाइसेंसी पिस्टल बरामद हुई है।

शिवचरण रोहिला मूल रूप से रामपुर मनिहारान क्षेत्र के गांव चंदनपुर के निवासी थे। वह पिछले करीब 20 वर्षों से थाना सदर बाजार क्षेत्र में नवादा रोड स्थित कमल विहार (जाली वाली फैक्टरी) में किराये पर रह रहे थे। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं। घटना के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए महापौर डॉ. अजय कुमार और पूर्व महापौर संजीव वालिया चंदनपुर गांव पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और सभी पहलुओं पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

पुलिस पर गिरी गाज! एक साथ 39 पुलिसवालों पर तगड़ा एक्शन

दरोगा भी नपे, एसओजी टीम भी हुई थी सस्पेंड; जांच में खुला ऐसा कांड

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश संभल जिले में पुलिस महकमे में लगातार प्रशासनिक सख्ती देखने को मिल रही है। गंभीर आरोपों और गोपनीय जांच के बाद पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पुलिस चौकी प्रभारी सहित 39 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। इस कदम से विभाग में हड़कंप की स्थिति है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार लाइन हाजिर किए गए कर्मियों में एक उपनिरीक्षक, 11 हेड कांस्टेबल और 27 कांस्टेबल शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई गोपनीय जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई है। लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मियों में थाना धनारी की सुल्तानगढ़ पुलिस चौकी के प्रभारी सुनील कुमार दिवाकर का नाम भी शामिल है। उनके अलावा जनपद के विभिन्न थानों में तैनात अन्य पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन भेजा गया है।

उल्लेखनीय है कि बीते दिनों एसपी ने भ्रष्टाचार और शिकायतों के आधार पर कड़ी कार्रवाई करते

हुए पूरी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) टीम को निलंबित कर दिया था। उस समय एसओजी प्रभारी मोहित कुमार को निलंबित करते हुए थाना रायसत्ती के प्रभारी रहे बोबिंद्र कुमार को नया एसओजी प्रभारी नियुक्त किया गया था।

सूत्रों के अनुसार मामला कोतवाली क्षेत्र के लाडम सराय इलाके से जुड़ा है। आरोप है कि एसओजी टीम ने मुरादाबाद जिले के बिलारी निवासी एक कबाड़ी को पकड़ा था। उसके पास से मोबाइल प्लेट से निकली सिल्वर धातु बरामद होने की बात कही गई।

पीड़ित कबाड़ी का आरोप है कि टीम उसे माल सहित चौधरी सराय पुलिस चौकी ले गई, जहां कमरे में बैठाकर उसके साथ मारपीट की गई। आरोप यह भी है कि बाद में एक स्थानीय कबाड़ी के माध्यम से रुपये लेकर उसे छोड़ दिया गया, जबकि बरामद धातु टीम ने अपने पास रख ली। कबाड़ी ने यह भी आरोप लगाया कि रिहाई के बाद धातु वापस करने के बदले अतिरिक्त रकम की मांग की गई। घटना की जानकारी सामने आने पर स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी फैल गई थी। मामले को मीडिया में प्रमुखता से उठाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष जांच कराई। जांच रिपोर्ट के आधार पर पहले एसओजी टीम के निलंबन और अब पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने जैसी कार्रवाइयां की गई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि विभागीय अनुशासन और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आगे भी सख्त कदम जारी रहेंगे।

जब-जब समाज की एकता खंडित हुई राष्ट्र पर संकट आया : मोहन भागवत

मेरठ **(एजेंसी)**। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्र निर्माण केवल किसी एक संगठन का नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। शताब्दी नगर स्थित माधवकुंज में आयोजित संवाद कार्यक्रम में खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए डॉ. भागवत ने सामाजिक एकता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में हर वर्ग, हर व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। भागवत ने कहा कि संघ किसी वर्ग विशेष के विरोध या स्पर्धा के लिए कार्य नहीं करता।

शताब्दीनगर स्थित माधवकुंज में मेरठ और ब्रज प्रांत के लगभग 950 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से संवाद करते हुए भागवत ने कहा कि भारत को मात्र भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, यह राष्ट्र भगवान श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी की परंपराओं से प्रेरित है। 'हिंदू' शब्द की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू कोई जाति नहीं, बल्कि एक विशेषण है, जो विविधता में एकता के भाव को अभिव्यक्त करता है। उन्होंने कहा, "पूजा पद्धतियां और देवी-देवता भिन्न हो सकते हैं, किंतु संस्कृति का आधार समरसता और एकता है। जब-जब समाज की एकता खंडित हुई, राष्ट्र पर संकट आया।

मेरठ को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की धरती बताते हुए भागवत ने 1857

के आंदोलन का उल्लेख किया और कहा कि इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में डॉ. हेडगेवार ने 1925 में संघ की स्थापना की। भागवत ने संघ से जुड़ने के पांच मंत्र भी बताए, जिनमें संघ को भीतर से समझना, अनुषांगिक संगठनों से जुड़ना, कार्यक्रमों में सहयोग, संवाद बनाए रखना और निस्वार्थ भाव से राष्ट्र के लिए कार्य करना शामिल है। उन्होंने खिलाड़ियों के सवालों के जवाब भी दिए। संवाद कार्यक्रम में भाग लेकर लौटे खिलाड़ियों ने बताया कि डॉ. भागवत ने अपने लगभग 50 मिनट के संबोधन में संघ की स्थापना से लेकर 100 वर्षों के सफर पर प्रकाश डाला और युवाओं से राष्ट्रहित में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों को कुछ संकल्प भी दिलाए और कहा कि खेल समाज को जोड़ने का सशक्त माध्यम है।

योगी सरकार बड़ा तोहफा, 2.51 लाख किसानों को दिया 285 करोड़ रुपये का फसल मुआवजा

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को 2.51 लाख से अधिक किसानों को फसल मुआवजे के रूप में 285 करोड़ रुपये प्रदान किए और कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न अनिश्चितताओं से बचाया जाए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सहायता वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो किसान अपनी फसलों का बीमा कराते हैं, वे आपदाओं से होने वाले नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता के हकदार हैं।

योगी ने कहा, "राज्य के 2.51 लाख किसान परिवारों को फसल क्षति मुआवजे के रूप में 285 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है। फसल बीमा यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को विपत्ति के समय में आर्थिक सहायता मिले। यह राशि हमारे 'अन्नदाता' के लिए एक सहारा है।" मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को चेक वितरित किए और कल्याणकारी योजनाओं और समय पर वित्तीय सहायता के माध्यम से किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं से उत्पन्न अनिश्चितताओं से बचाया जाए और कल्याणकारी पहल पारदर्शी तरीके से लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे।

हाथ लगाते ही पापड़ की तरह उखड़ने लगी सड़क

ग्रामीणों ने दिखाई भ्रष्टाचार की हकीकत अब मिल रही उठा लेने की धमकी

लखनऊ **(एजेंसी)**। प्रदेश के झांसी जिले से भ्रष्टाचार का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जो सरकारी दावों की धज्जियां उड़ा रहा है। जहां के गरौठा तहसील में बन रही एक सड़क इतनी घटिया क्वालिटी की है कि ग्रामीण उसे अपने हाथों से मिट्टी की तरह उखाड़ रहे हैं। लाखों की लागत से बन रही इस सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो गया है।

मामला ग्राम बरमाइन से ककरबई के बीच का है, जहां करीब 6 किलोमीटर लंबी सड़क का मरम्मत कार्य चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार मानकों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सड़क बनाने से पहले न तो सफाई की गई और न ही सही बेस तैयार किया गया। मिट्टी और गोबर के ऊपर ही डामर (लुक) डाल दिया गया है, जिसके कारण सड़क हाथ लगाते ही उखड़ रही है।

हैरानी की बात यह है कि जब ग्रामीणों ने इस भ्रष्टाचार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, तो उन्हें डराने-धमकाने का सिलसिला शुरू हो गया। एक ग्रामीण ने रोष व्यक्त करते हुए कहा

कि हमने मुख्यमंत्री जी को हकीकत दिखाने के लिए वीडियो बनाया, तो अब हमें धमकियां मिल रही हैं कि रात में घर से उठा लेंगे। धमकी देने वाला शख्स यहीं काम करा रहा है।

वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। गरौठा एसडीएम सुनील कुमार ने मामले का संज्ञान लेते हुए बताया कि यह सड़क लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वीडियो हमारे संज्ञान में है। इसकी जांच के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जा रही है। अगर ठेकेदार की लापरवाही मिली तो भारी जुर्माना लगेगा और विभाग की गलती पाए जाने पर अधिकारियों पर भी एक्शन होगा।

एआई इम्पैक्ट समिट में भारत का डंका पीएम मोदी के विजन पर 88 देशों ने लगाई मुहर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी तक आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के घोषणापत्र पर कुल 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हस्ताक्षर किए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए वैष्णव ने कहा कि 86 देशों और दो अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संपूर्ण विश्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानव-केंद्रित एआई दृष्टिकोण को स्वीकार किया है और एआई संसाधनों के लोकतंत्रीकरण पर सहमति व्यक्त की है ताकि एआई के लाभ और तकनीक विश्व भर में समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सकें।

वैष्णव ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि एआई इम्पैक्ट समिट की घोषणा पर कुल 88 देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसे अब जारी किया जा रहा है। इनमें से 86 देशों और दो अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। संपूर्ण विश्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानव-केंद्रित एआई दृष्टिकोण को स्वीकार किया है। सभी ने एआई संसाधनों के लोकतंत्रीकरण पर सहमति व्यक्त की है ताकि एआई के लाभ और प्रौद्योगिकी विश्व भर में समाज के सभी वर्गों तक पहुंच सकें। सभी ने इसे स्वीकार किया है।

भारत एआई इम्पैक्ट समिट, ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है, जो एआई की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डालता है और 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' (सभी का कल्याण, सभी का सुख) के राष्ट्रीय दृष्टिकोण और मानवता के लिए एआई के वैश्विक सिद्धांत के अनुरूप है। यह शिखर सम्मेलन एआई के शासन, सुरक्षा और सामाजिक प्रभाव पर वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित हो रही अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया का एक हिस्सा है।

भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। यह 16 फरवरी को शुरू हुआ और 20 फरवरी, 2026 को समाप्त हुआ। इस शिखर सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में दुनिया भर के सरकारी नीति निर्माता, उद्योग के एआई विशेषज्ञ, शिक्षाविद, प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तक और नागरिक समाज के प्रतिनिधि एक साथ आए। भारत एआई इम्पैक्ट समिट, जो ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है, एआई की परिवर्तनकारी क्षमता पर विचार करता है, जो 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' (सभी के लिए कल्याण, सभी के लिए सुख) की राष्ट्रीय दृष्टि और मानवता के लिए एआई के वैश्विक सिद्धांत के अनुरूप है।

दुनिया में ईसाई, इस्लामिक, यहूदी और बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता : अनु कपूर

मुम्बई **(एजेंसी)**। जाने माने अभिनेता अनु कपूर ने राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र की बहस को केंद्र में ला खड़ा किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रगान से पहले 'वंदे मातरम्' के सभी छह श्लोक गाने के निर्देश का उन्होंने खुलकर स्वागत करते हुए इसे 'अद्भुत और ऐतिहासिक निर्णय' बताया है। अनु कपूर ने कहा कि यह राष्ट्र की चेतना के लिए शुभ संकेत है। अनु कपूर ने साथ ही वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत को शांति, करुणा और विश्वकल्याण का संदेश देने वाला बताते हुए कहा कि भारतीय सभ्यता की आत्मा अहिंसा और सहअस्तित्व में विश्वास करती है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की कामना करने वाला समाज किसी के लिए खतरा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि अगर हिंदू प्रार्थना करता है तो वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समूचे विश्व के लिए मंगलकामना करता है। ऐसे में हिंदू पहचान से डर क्यों? उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू-मुस्लिम विभाजन की कथित खाई दरअसल राजनीतिक स्वार्थों की उपज है।

उन्होंने कहा कि जब दुनिया

में ईसाई राष्ट्र हो सकते हैं, मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, यहूदी राष्ट्र हो सकते हैं, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? अनु कपूर ने कहा कि समय आ गया है कि हिंदू एकता कायम हो और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाये।

दूसरी ओर, अनु कपूर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल फिर उठने लगा है कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए? देखा जाये तो भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक जड़ें हिंदू सभ्यता में निहित हैं। यहां की परंपराएं, त्योहार, जीवन-दर्शन और सामाजिक संरचना उसी धरोहर से निर्मित हुए हैं। हिंदू राष्ट्र का अर्थ किसी अन्य धर्म के प्रति घृणा नहीं, बल्कि उस मूल सांस्कृतिक पहचान को संवैधानिक स्वीकृति देना है, जिसने इस भूमि को आकार दिया।

यह भी सत्य है कि 'धर्मनिरपेक्षता' की आड़ में अक्सर तुष्टिकरण की राजनीति ने बहुसंख्यक समाज को अपराधबोध में जीने पर मजबूर किया है। यदि भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित करता है, तो इसका संदेश होगा कि यह राष्ट्र अपनी जड़ों पर गर्व करता है। यह वैसा ही होगा जैसे कई इस्लामी या ईसाई राष्ट्र अपनी धार्मिक पहचान के साथ भी लोकतांत्रिक ढांचा बनाए रखते हैं। इसके अलावा, हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ कर सकती है। जब पहचान स्पष्ट होती है, तब भ्रम कम होता है। अनु कपूर का आह्वान इसी स्पष्टता की मांग करता है यानि धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जाए, लेकिन अपनी मूल पहचान से समझौता किए बिना।

जहां तक हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आरएसएस के विचार की बात है तो हम आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत समय समय पर यह स्पष्ट करते रहे हैं कि भारत प्राचीन काल से ही हिंदू राष्ट्र है भले संविधान में इस प्रकार का कोई औपचारिक दर्जा ना हो लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र ही है।

छत्तीसगढ़ फाइनल वोटर लिस्ट जारी, चार महीने के महाअभियान के बाद 1.87 करोड़ मतदाता तैयार

रायपुर **(एजेंसी)**। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने छत्तीसगढ़ की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करके एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक उपलब्धि हासिल की, जो एक गहन विशेष संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया का समापन है। 1 जनवरी को पात्रता तिथि मानते हुए, राज्य में अब 1, 87, 30, 914 पंजीकृत मतदाता हैं - मसौदा सूची से 2, 34, 994 की शुद्ध वृद्धि। यह अद्यतन आगामी चुनावों से पहले प्रत्येक पात्र नागरिक की आवाज को महत्व देने के अथक प्रयासों को दर्शाता है। घर-घर सत्यापन ने प्रक्रिया को शक्ति प्रदान की।

27 अक्टूबर, 2025 को शुरू किए गए एसआईआर अभियान के केंद्र में 27, 196 समर्पित बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) थे, जो घर-घर जाकर मतदाता सूची की जाँच करने में जुट गए। उन्होंने चार गहन महीनों के दौरान पूरे राज्य में प्रपत्र वितरित किए, मतदाताओं का मानचित्रण किया और विवरणों का सत्यापन किया। 23 दिसंबर, 2025 से 22 जनवरी, 2025 तक संशोधनों, विलोपनों और सुधारों के लिए बड़ी संख्या में दावे प्राप्त हुए, जिनमें से सभी का समाधान 14 फरवरी तक कर दिया गया, जिससे सटीकता और समावेशिता सुनिश्चित हुई।

छत्तीसगढ़ की सफलता चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए जा रहे राष्ट्रव्यापी मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) के अनुरूप है, जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी,

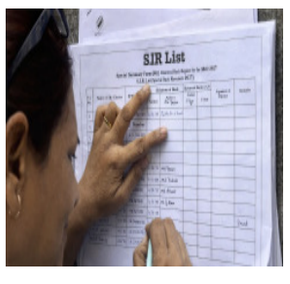

राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। 19 फरवरी को, चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर आदि जैसे 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले एसआईआर के दूसरे चरण के लिए तैयार रहने का आग्रह किया, और सुचारू क्रियान्वयन के लिए समय पर तैयारियों पर जोर दिया।

यह कार्यान्वयन न केवल छत्तीसगढ़ के चुनावी आधार को मजबूत करता है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम करता है, जिससे भागीदारी बढ़ती है और धोखाधड़ी पर अंकुश लगता है। भारत आगामी चुनावों की ओर देख रहा है, ऐसे संशोधन चुनाव आयोग की मजबूत, पारदर्शी मतदाता सूचियों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं, जिससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लाखों लोगों को सशक्त बनाया जा सके।

डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार मिनीवैन, 5 यात्रियों की मौत, 6 घायल

अहमदाबाद **(एजेंसी)**। गुजरात के वलसाड जिला अंतर्गत कपराडा तालुका में कुंभघाट के पास आज एक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। एक तेज रफ्तार ईको कार और ट्रक के बीच हुई आमने-सामने की भीषण टक्कर में पांच लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और वह धातु के ढेर में तब्दील हो गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला।

यह हादसा कपराडा-नानापोंधा राजमार्ग पर घटित हुआ। जानकारी के अनुसार कार में सवार सभी लोग अंबा जंगल गांव के निवासी थे और किसी निजी काम से कपराडा से नानापोंधा की ओर जा रहे थे। कुंभघाट के पास सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने उनकी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मृतकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस दुर्घटना के कारण हाईवे पर घंटों तक लंबा जाम लगा रहा, जिसे क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर सुचारू किया गया।

विवाह धोखाधड़ी के शिकार हुए बिट्टू बजरंग दुल्हन नहीं मिली तो पुलिस में कराई एफआईआर

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। नूह हिंसा के सिलसिले में पहले भी सुर्खियों में रहे बिट्टू बजरंग एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार विवाद एक कथित विवाह धोखाधड़ी से जुड़ा है। बजरंग ने अपने पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों पर शादी करवाने के वादे पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उनकी शिकायत के अनुसार, एक बिचौलिए के माध्यम से 12 लाख रुपये में शादी तय की गई थी, लेकिन जब वे बारात लेकर अलीगढ़ पहुंचे, तो न तो दुल्हन मिली और न ही शादी की कोई व्यवस्था।

शिकायत के अनुसार, बजरंग ने अपने पड़ोसी के रिश्तेदार बंटी को बताया था कि वह शादी करना चाहते हैं और एक उपयुक्त वर की तलाश में हैं। बंटी ने उन्हें रानी नाम की एक महिला से मिलवाया, जिसने दावा किया कि वह शादी करवा सकती है। बताया जाता है कि बजरंग को संभावित दूल्हों से मिलने के लिए तीन बार अलीगढ़ बुलाया गया, लेकिन उन्होंने किसी को भी अंतिम रूप नहीं दिया। बाद में, बंटी ने उन्हें अपनी पसंद की एक लड़की की तस्वीर भेजी। 5 सितंबर, 2025 को, बंटी और रानी कथित तौर पर लड़की और उसके परिवार को बजरंग के घर लाए और 7 फरवरी को शादी तय की गई।

शादी से पहले, बजरंग ने 6 फरवरी को दुल्हन के कपड़ों और तैयारियों के लिए 30, 000 रुपये भेजे। उनका दावा है कि अन्य भुगतान भी किए गए, जिससे कुल राशि 1.20 लाख रुपये हो गई। हालांकि, जब वह तय तारीख पर

बारात लेकर अलीगढ़ पहुंचे, तो आरोपी वहां मौजूद नहीं थे और उनके मोबाइल फोन बंद थे। बजरंग ने बताया कि जब उन्होंने किसी तरह लड़की से संपर्क किया, तो उसने कहा कि उसे शादी की कोई जानकारी नहीं है। उन्हें दुल्हन के बिना ही घर लौटना पड़ा।

बजरंगी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरू में कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पुलिस आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद, सारण पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की कि जांच जारी है। अधिकारी मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं, जिसमें वायरल हुई ऑडियो क्लिप भी शामिल है, जिसमें कथित तौर पर आरोपियों को वित्तीय व्यवस्थाओं पर चर्चा करते हुए सुना जा सकता है।

'यह एक छूटा अवसर थी', टी20 विश्व कप से बाहर होने पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल ने जताया अफ़सोस

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। ओमान के खिलाफ अपने आखिरी ग्रुप स्टेज टी20 विश्व कप मैच में जीत के बाद, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने अपने अभियान को एक चूके हुए अवसर के रूप में गंवाने पर अफसोस जताया और कहा कि ड्रेसिंग रूम अपने प्रदर्शन से बेहद निराश है। ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को पालेकेले में ओमान को करारी शिकस्त देते हुए एक बड़ी जीत हासिल की और दो जीत और दो हार के साथ अपने अभियान का शानदार अंत किया।

लेकिन जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ उनके खराब प्रदर्शन ने ऑस्ट्रेलियाई टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की स्थिति और इस बात पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या वे इस प्रारूप को गंभीरता से लेते हैं या नहीं। टूर्नामेंट में आने से पहले, प्रमुख तेज गेंदबाज जोश हेज़लवुड और पैट कमिंस चोटों के कारण बाहर थे, और कप्तान मार्श ग्रोइन इंजरी के कारण दो मैच नहीं खेल पाए। स्टीव स्मिथ को उनके स्थान पर टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। मैच के बाद मार्श ने कहा कि शायद बस एक छूटे हुए अवसर का एहसास है (उनके मन में अभी क्या चल रहा है, इस बारे में बात करते हुए)। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, ड्रेसिंग रूम बेहद निराश है। हर टीम की तरह, हमने इसके लिए दो साल तक मेहनत की थी। दुर्भाग्य से, कुछ अहम मैचों में हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए - और यही तो टूर्नामेंट का खेल है। जिम्बाब्वे के खिलाफ जैसा मैच हारने पर अचानक आप दबाव में आ जाते हैं। उन्हें श्रेय जाता है, उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन हम अभी बहुत निराश हैं। मार्श ने कहा कि परिस्थितियाँ मुख्य समस्या नहीं थीं, और उनके पास धीमी परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त खिलाड़ी थे। उन्होंने अफसोस जताया कि उनकी टीम सबसे अहम समय पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई।

उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि यहीं पर नेतृत्व महत्वपूर्ण हो जाता है (यही सवाल है - आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिक्रिया केवल भावनात्मक न होकर आगे चलकर रचनात्मक हो?)। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और खिलाड़ियों के समूह के नेता आपस में बैठकर स्थिति का सही आकलन करेंगे। खिलाड़ी और एक टीम के रूप में, हम देखेंगे कि हम कैसे लगातार सुधार कर सकते हैं। अगर हमें एक समूह के रूप में दूसरा मौका मिलता है, तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इस अनुभव से और बेहतर बनें। असफलता से हमेशा सबक मिलता है। अभी दुख हो रहा है और जिस तरह से सब कुछ हुआ उससे हम निराश हैं। लेकिन हम घर जाएंगे, ईमानदारी से आत्मचिंतन करेंगे और आगे बढ़ेंगे।

टी20 वर्ल्ड कप : भारत में न खेलने के फैसले पर बांग्लादेशी कोच का बड़ा खुलासा, फिर गरमाया विवाद

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश के हटने के फैसले पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बांग्लादेश के पूर्व स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नज़रुल ने दावा किया था कि टूर्नामेंट से नाम वापसी का फैसला टीम के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने मिलकर लिया था। हालांकि, इस बयान को बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सीनियर असिस्टेंट कोच मोहम्मद सलाहुद्दीन ने सिरे से खारिज कर दिया है।

मोहम्मद सलाहुद्दीन ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहाः 'आसिफ नजरुल का बयान पूरी तरह गलत है। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होकर वह इतना साफ झूठ कैसे बोल सकते हैं, यह समझ से परे है। फैसला सरकार द्वारा लिया गया था और टीम को टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा न लेने के लिए मजबूर किया गया था। इसमें खिलाड़ियों या कोच की कोई भूमिका नहीं थी।'

उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ी खुद टूर्नामेंट नहीं खेल पाने को लेकर तनाव में थे और दो खिलाड़ी तो गंभीर रूप से बीमार भी पड़ गए थे। सलाहुद्दीन ने आरोप लगाया कि अब सारा दोष खिलाड़ियों और कोच पर डाला जा रहा है, जबकि असल में यह फैसला ऊपर से लिया गया था।

बांग्लादेश पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा था। लेकिन बाद में उसने भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया। विवाद की शुरुआत आईपीएल 2026 के दौरान हुई, जब बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता नाइटराइडर्स से रिलीज़ कर दिया गया। बताया गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के चलते हालात संवेदनशील थे।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने फ्रेंचाइजी को उन्हें रिलीज़ करने का निर्देश दिया था। इसके बाद बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत आने से इनकार कर दिया और मैचों को किसी अन्य देश में शिफ्ट करने की मांग की।

मामला आईसीसी तक पहुंचा। आईसीसी ने सर्वे और सुरक्षा आकलन के बाद कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में किसी तरह का खतरा नहीं होगा। आईसीसी ने बांग्लादेश को आश्वासन भी दिया और अपना रुख बदलने के लिए समयसीमा तय की। लेकिन बांग्लादेश अपने फैसले पर अड़ा रहा।

आखिरकार आईसीसी ने बड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया।

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार का आलोचकों को करारा जवाब, अभिषेक शर्मा का किया बचाव

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारतीय पुरुष टी20ई टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 के पहले मैच से पहले खराब फॉर्म से जूझ रहे बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का समर्थन किया। भारत के धुआंधार सलामी बल्लेबाज अभिषेक ने टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप स्टेज में तीन मैच खेले हैं और अभी तक एक भी रन नहीं बना पाए हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में लगातार तीन मैचों में शून्य पर आउट हुए हैं।

खराब फॉर्म के बावजूद, भारतीय टीम के कप्तान ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सुपर 8 के मुकाबले से पहले अभिषेक शर्मा का समर्थन किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे अभिषेक की फॉर्म को लेकर चिंतित हैं, तो भारतीय टीम के कप्तान ने कहा कि वे उन लोगों को लेकर चिंतित हैं जो सलामी बल्लेबाज की फॉर्म को लेकर परेशान हैं। सूर्यकुमार ने कहा कि क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते-जाते रहते हैं और फिलहाल टीम को अभिषेक से उम्मीद है कि वे अपनी खास शैली में खेलें। सूर्यकुमार ने यह भी कहा कि पिछले साल अभिषेक शर्मा ने बाकी भारतीय बल्लेबाजों की कमी पूरी की थी, और इस बार बाकी बल्लेबाजों की बारी है।

सूर्यकुमार यादव ने कहा कि अभिषेक की फॉर्म को लेकर जो लोग चिंतित हैं, मुझे भी उनकी चिंता है। अभी तक उन्होंने रन नहीं बनाए हैं, लेकिन जब वे रन बनाते हैं, तो आपने देखा ही होगा कि क्या होता है। यह एक टीम खेल है; ऐसे दौर आते-जाते रहते हैं। फिलहाल टीम को उनसे उम्मीद है कि वे अपनी खास शैली में खेलें, और वे यही कोशिश कर रहे हैं। अगर वे सफल होते हैं, तो बहुत अच्छा। अगर नहीं, तो हम उनकी कमी पूरी करने के लिए तैयार हैं। पिछले साल उन्होंने हमारी कमी पूरी की थी। इस बार हम उनकी कमी पूरी करेंगे।

सूर्यकुमार यादव ने अब तक टी20 विश्व कप 2026 में विकेटों के बारे में बात करते हुए कहा कि भारतीय टीम किसी भी तरह के विकेट के अनुकूल ढलने के लिए तैयार है, और उन्होंने कहा कि उनके पास इतना क्रिकेट अनुभव है कि वे समझ सकें कि मैच के विभिन्न चरणों में बल्लेबाजी करते समय टीम को किस प्रकार का क्रिकेट खेलने की आवश्यकता है।

प्रो लीग होबार्ट : स्पेन ने भारत को 2-0 से हराया

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। भारत पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम को एफआईएच प्रो लीग के होबार्ट लेग के पहले मुकाबले में स्पेन की पुरुष राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। करीबी मुकाबले में स्पेन ने अपने मौकों को भुनाया, जबकि भारतीय टीम आक्रामक खेल के बावजूद गोल करने में नाकाम रही।

स्पेन के लिए इग्नासियो अबाजो ने छठे मिनट में गोल कर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। भारतीय टीम ने तेज पासिंग के साथ मैच की शुरुआत की, लेकिन स्पेन का काउंटर-अटैक प्रभावी रहा। पहले क्वार्टर के अंत में अभिषेक के दमदार शॉट को स्पेनिश गोलकीपर लुइस कैलजाडो ने शानदार बचाव कर रोक दिया।

दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। 24वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर भारतीय गोलकीपर सूरज करकेरा ने बेहतरीन बचाव किया। हाफटाइम तक स्पेन 1-0 से आगे था।

तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में स्पेन ने दबाव बनाए रखा। इग्नासियो कोबोस ने 36वें मिनट में सर्कल के अंदर से गोल कर स्पेन की बढ़त 2-0 कर दी। इसके बाद स्पेन ने लगातार दबाव बनाया और तीसरे क्वार्टर में पांच पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन भारतीय रक्षापंक्ति ने और नुकसान नहीं होने दिया। चौथे क्वार्टर में भारत ने आक्रामक रुख अपनाया और पहला पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किया, लेकिन उसे गोल में नहीं बदल सका। भारतीय गोलकीपर होनेनहल्ली शशिकुमार मोहित ने भी शानदार बचाव किया।

अंतिम चार मिनट में भारत ने गोलकीपर को हटाकर अतिरिक्त आउटफील्ड खिलाड़ी उतारा, लेकिन स्पेन की मजबूत रक्षा पंक्ति को भेदने में असफल रहा और मैच 0-2 से समाप्त हुआ।

शुद्ध बाजार उधारी वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी के तीन प्रतिशत तक आएगी : आरबीआई

मुंबई **(एजेंसी)**। सरकार की शुद्ध बाजार उधारी में गिरावट से निजी क्षेत्र के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होने की संभावना है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के शुक्रवार को जारी मासिक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। आरबीआई बुलेटिन के मुताबिक, केंद्र सरकार की शुद्ध बाजार उधारी वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी के तीन प्रतिशत तक घटाने का प्रस्ताव है, जो महामारी-पूर्व स्तर की ओर धीरे-धीरे वापसी का संकेत है। इस साल के लिए 17.3 लाख करोड़ रुपए की सकल बाजार उधारी का प्रस्ताव कई लोगों की अपेक्षाओं से अधिक माना गया है। इससे निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध संसाधनों और बजट दिवस पर बाजार में गिरावट को लेकर चिंता हुई।

आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, शुद्ध बाजार उधारी महामारी से पहले वित्त वर्ष 2019-20 में 4.73 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 2.4 प्रतिशत) थी। यह वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़कर 10.33 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 5.2 प्रतिशत) हो गई थी और इसके बाद के वर्षों में महामारी पूर्व स्तर से अधिक रही, जो वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी का 4.1 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2023-24 में 3.9 प्रतिशत थी। बुलेटिन के मुताबिक, 'केंद्र सरकार की शुद्ध बाजार उधारी की जीडीपी के अनुपात में क्रमिक गिरावट महामारी-पूर्व स्तर की ओर निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाने में मदद करेगी।' वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट में सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 4.4 प्रतिशत) और शुद्ध बाजार उधारी 11.7 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का तीन प्रतिशत) रहने का लक्ष्य है। वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध बाजार उधारी 11.63 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 3.5 प्रतिशत) और वित्त-वर्ष 2025-26 में 11.32 लाख करोड़ रुपए (जीडीपी का 3.2 प्रतिशत) थी। बुलेटिन के मुताबिक, शुद्ध बाजार उधारी में कमी आने से घरेलू वित्तीय बाजार पर दबाव कम होगा।

घरों का डिजाइन बनाते समय लोगों की खरीद क्षमता का ध्यान रखा जाए : गडकरी

नागपुर **(एजेंसी)**। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि निर्माण क्षेत्र में डिजाइन तैयार करते समय लोगों की खरीद क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। गडकरी ने कहा कि इस समय देश में सबसे अधिक जरूरत कम लागत वाले और किफायती आवास की है। केंद्रीय मंत्री ने यह बात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स की तरफ से आयोजित 'डिजाइन शोकेस एंड कॉन्फ्लुएंस 3.0' कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट देश के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है, जो बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करता है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र जीएसटी के माध्यम से राज्यों और केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व भी देता है। गडकरी ने कहा, 'निर्माण योजनाएं बनाते समय आम लोगों की आय और खरीद क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है। वर्तमान समय में सबसे अधिक जरूरत कम लागत वाले और किफायती घरों की है।' इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निर्माण क्षेत्र को उत्पादन लागत कम करने के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नए निर्माण डिजाइन, नवाचार एवं शोध की जरूरत पर भी बल दिया।

भारत का तेल आयात रणनीति में बदलाव ऊर्जा सुरक्षा के प्रति बड़े बदलाव का संकेत : ग्लोबलडेटा

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। कच्चे तेल के आयात को लेकर भारत की रणनीति केवल 'सस्ता तेल' खरीदने तक सीमित न रहकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने के लिए रणनीतिक कदम उठाने तक पहुंच गई है। विश्लेषक फर्म ग्लोबलडेटा ने शुक्रवार को यह बात कही। विश्लेषक फर्म ने कहा कि भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग एक-चौथाई हिस्सा तेल से पूरा करता है और अपनी जरूरत का 87 प्रतिशत तेल दूसरे देशों से खरीदता है। इसे देखते हुए, भारत अब एक नई रणनीति पर काम कर रहा है।

इसके तहत वह अंतरराष्ट्रीय नियमों के पालन, अलग-अलग देशों से तेल खरीदने और अमेरिका के साथ ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता भारत के बारे में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि इसकी मांग 2024 के 55 लाख बैरल प्रति दिन से बढ़कर 2035 तक 80 लाख बैरल प्रति दिन हो जाएगी। घरेलू स्तर पर तेल खोज जारी रहने के बावजूद 2035 तक आयात पर निर्भरता बढ़कर 92 प्रतिशत हो सकती है, जिससे बाहरी आपूर्ति के झटकों का खतरा बढ़ जाएगा।

ग्लोबलडेटा में आर्थिक शोध के सह परियोजना प्रबंधक अर्णब नाथ ने कहा कि मांग और घरेलू उत्पादन के बीच बढ़ता अंतर आपूर्ति के आधार को व्यापक बनाने के प्रयासों को प्रेरित कर रहा है। इसका उद्देश्य किसी एक या राजनीतिक रूप से सीमित आपूर्ति गलियारों पर निर्भरता कम करना है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के कच्चे तेल के स्रोतों में 2022 से काफी बदलाव आया है। यूक्रेन संघर्ष से पहले भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 2.7 प्रतिशत थी, जो रियायती दरों के कारण 2024 में बढ़कर 25.9 प्रतिशत हो गई।

हालांकि, व्यापारिक नियमों और प्रतिबंधों के कड़े होने के बीच जनवरी 2026 में रूस से आयात में सालाना आधार पर 40 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। इसी समय, अमेरिका और वेनेजुएला फिर से भारत के कच्चे तेल के आयात समूह का हिस्सा बने हैं। ग्लोबलडेटा ने कहा कि वेनेजुएला से मात्रा सीमित रहने की उम्मीद है, लेकिन उन्हें एक सामरिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। फर्म ने यह भी कहा कि यह बदलाव ईरान से संबंधित व्यापार पर अमेरिकी शुल्क की धमकियों से भी प्रभावित है।

अमेरिका में शुल्क से जुड़ी घटनाओं का अध्ययन कर रही सरकार : वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली **(एजेंसी)**। वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि सरकार अमेरिका में सीमा शुल्क से जुड़े ताजा घटनाक्रम और उसके संभावित प्रभावों का अध्ययन कर रही है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'शुक्रवार को सीमा शुल्क के बारे में आया अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का फैसला हमारे संज्ञान में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस संबंध में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया है।'

बयान में कहा गया, 'अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कुछ कदमों की घोषणा की गई है। हम इन सभी घटनाक्रमों का उनके प्रभावों के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं।' ट्रंप की तरफ से पिछले साल भारत समेत करीब 60 देशों के खिलाफ जारी शुल्क आदेशों को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को रद्द घोषित कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने 10 प्रतिशत वैश्विक सीमा शुल्क लगाने की घोषणा कर दी है।

ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर भी 25 प्रतिशत शुल्क और रूसी तेल खरीदने के लिए 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगा दिया था। इस तरह अगस्त, 2025 से भारतीय उत्पादों के आयात पर अमेरिका में कुल 50 प्रतिशत शुल्क लग रहा था। हालांकि इस साल फरवरी की शुरुआत में भारत और अमेरिका ने एक अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनने की घोषणा की। इसके तहत अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत करने की बात कही है।

निक जोनास ने हाथ में पहना प्रियंका का मंगलसूत्र प्रशंसक बोले- हमारे राष्ट्रीय जीजू ने दिल जीत लिया!

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म प्राइम वीडियो पर 'द ब्लफ' जल्द रिलीज होने वाली है। फिल्म प्रमोशन के दौरान प्रियंका चोपड़ा के साथ निक जोनास भी नजर आएं। निक जोनास सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें वे उनकी फिल्म के किरदार 'ब्लडी मैरी' से प्रेरित कॉकटेल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फैंस ने तुरंत गौर किया कि उन्होंने मंगलसूत्र को ब्रेसलेट की तरह पहना हुआ था और प्रियंका की संस्कृति के प्रति सम्मान जताते हुए इस भाव की सराहना की। फिल्म के प्रीमियर पर भी निक ने वही ब्रेसलेट पहना था, जैसा कि रेड कार्पेट की तस्वीरों में साफ दिख रहा है।

इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो में निक प्रियंका के फिल्म के किरदार से प्रेरित कॉकटेल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, 'दोस्तों, आज प्रियंका की फिल्म 'द ब्लफ' का अमेजन प्राइम पर प्रीमियर है। यह कमाल की फिल्म है, मैंने इसे दो बार देखा है। उनके किरदार का नाम ब्लडी मैरी है, इसलिए मैं ब्लडी मैरी बनाऊंगा।' इसके बाद सिंगर ने कॉकटेल बनाया और उसमें काफी सारा टैबास्को सॉस मिलाया, जो प्रियंका के व्यक्तित्व से मेल खाता था और फैंस को निक का यह अंदाज बेहद पसंद आया। बाद में उन्होंने प्रियंका को यह ड्रिंक पेश किया जिसे प्रियंका ने बहुत पसंद किया और कहा, 'आपके पास बेहतरीन रेसिपी हैं।'

वायरल वीडियो में फैंस ने तुरंत देखा कि निक ने मंगलसूत्र का ब्रेसलेट पहना हुआ है और उनके इस नेक भाव की सराहना की। एक यूजर ने लिखा, 'अरे यार, उन्होंने मंगलसूत्र का ब्रेसलेट पहना है।' एक अन्य टिप्पणी में लिखा था, 'निक जीजू सबसे अच्छे हैं।' एक और प्रशंसक ने कहा, 'अगर आप उस मंगलसूत्र पर ध्यान दें, तो निक जीजू एक ग्रीन फॉरेस्ट की तरह हैं। इस समय टिप्पणियों में प्रशंसा की बाढ़ आ गई, प्रशंसकों ने उन्हें प्रियंका की संस्कृति के प्रति सहायक और गहरा सम्मान दिखाने वाला बताया।

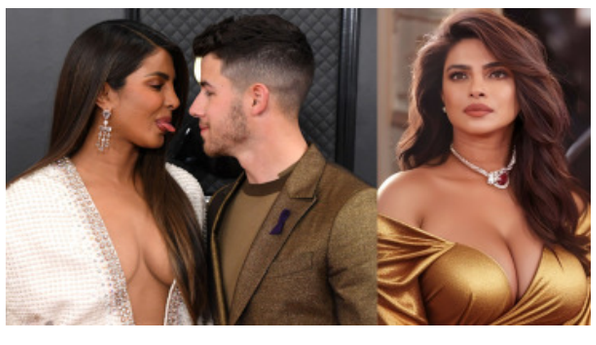

द ब्लफ एक रोमांचक एक्शन-एडवेंचर थ्रिलर है जिसकी कहानी 19वीं सदी के समय के कैरिबियन में घटित होती है। यह फिल्म एर्सेल 'ब्लडी मैरी' बॉडेन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार प्रियंका ने निभाया है। वह एक पूर्व समुद्री डाकू रानी की भूमिका निभाती हैं, जिसने अपने हिंसक अतीत को पीछे छोड़कर एक दूर से द्वीप पर अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिताने का प्रयास किया है।

प्रियंका और कार्ल के साथ-साथ, इस्माइल क्रूज कॉर्डोवा, सफिया ओकले-ग्रीन और टेमुएरा मॉरिसन भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं, जो भयंकर लड़ाइयों और व्यक्तिगत मुक्ति की कहानी को जीवंत करते हैं। द ब्लफ का निर्देशन फ्रैंक ई. फ्लावर्स ने किया है, जो जॉ बॉलारिनी के साथ सह-लिखित है और 25 फरवरी 2026 को प्राइम वीडियो पर इसका प्रीमियर होने वाला है।

विजय-रश्मिका की शादी का आलीशान निमंत्रण बॉक्स वायरल, कार्ड के साथ भेजे खास तोहफे!

इन दिनों विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी चर्चे काफी सुर्खियों में है। कुछ समय पहले शादी के कार्ड की झलक सामने आई थी, अब इन्विटेशन बॉक्स का वीडियो सामने आया है। गौरतलब है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरें इन दिनों बी-टाउन का हॉट टॉपिक बना हुआ है। इस बीच, उनकी शादी में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। हाल ही में विजय देवरकोंडा के सजे हुए घर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। अब वेडिंग इन्विटेशन बॉक्स का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दिलचस्प की बात है कि अतिथियों को क्या-क्या तोहफे दे रहे हैं रश्मिका और विजय।

बताया जा रहा है कि विजय और रश्मिका का वेडिंग इनविटेशन पारंपरिक कार्डों के बजाय एक प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स वाला है। इस वेडिंग इनविटेशन बॉक्स में कपल से जुड़ी चीजें की गई हैं। सोशल मीडिया पर इस प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे पता चलता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या-क्या है।

इस बॉक्स की सबसे खास बात है कि नेशनल क्रश नाम का परफ्यूम, जो रश्मिका मंदाना के फेमस टाइटल से संबंधित है और उनके हाल ही में लॉन्च हुए परफ्यूम ब्रांड को समर्पित है। इस बॉक्स में हैंड क्रीम और फुट क्रीम भी एड ऑन है। बॉक्स को पर्सनल टच देने के लिए विजय देवरकोंडा के कपड़ों के ब्रांड से जुड़ी रॉडी टी-शर्ट भी शामिल है। इसके साथ ही इस बॉक्स में काजू और मिठाई का डिब्बा भी शामिल है।

वायरल वीडियो पर कई सारे कमेंट्स दिख रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि यह बॉक्स मीडिया के लिए है। विजय और रश्मिका के गेस्ट के लिए इससे बेहतर इन्विटेशन बॉक्स है। कुछ यूजर ने लिखा है कि यहां पर ब्रैंड प्रमोशन कर लिया।

कुछ दिन पहले इन दोनों की शादी का निमंत्रण पत्र भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस कार्ड से जानकारी मिली थी कि दोनों 26 फरवरी को विवाह बंधन में बंधने वाले हैं। वहीं, निमंत्रण पत्र में 4 मार्च को आयोजित होने वाले उनके रिसेप्शन का भी उल्लेख किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस रिसेप्शन समारोह में फिल्म इंडस्ट्री की कई मशहूर हस्तियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।